● वर्ष-3
● अंक-174
रायपुर, गुरुवार 29 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› कोलकाता के नजदीक हिल....

महाराष्ट्र में मोदी ने फिर भरी हुंकार, बोले-

अबकी बार... 400 पार, इंडी गठबंधन पर साधा निशाना

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों को 21 हजार करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की और साथ ही महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं 10 साल पहले जब 'चाय पर चर्चा' करने यवतमाल आया था, तो आपने बहुत आशीर्वाद दिया और देश की जनता ने एनडीए को 300 पार पहुंचा दिया। फिर मैं 2019 में फरवरी के महीने में ही यवतमाल आया था। तब भी आपने हम पर खूब प्रेम बरसाया। देश ने भी तब एनडीए को 350 पार करा दिया। आज जब 2024 के चुनाव से पहले मैं विकास के उत्सव में शामिल होने आया हूं, तब पूरे देश में एक ही आवाज गूंज रही है। अबकी बार... 400 पार! नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश बनाने के लिए, देशवासियों का जीवन बदलने के लिए एक मिशन लेकर निकले हुए लोग हैं। इसलिए बीते 10 वर्ष में जो कुछ किया, वो आने वाले 25 वर्ष की नींव है। मैंने भारत के कोने-कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण-कण, जीवन का क्षण-क्षण समर्पित है। उन्होंने जौर देते हुए कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए चार सबसे बड़ी प्राथमिकता है- गरीब, किसान, नौजवान और नारीशक्ति। ये चारों सशक्त हो गए, तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यहीं महाराष्ट्र से ही थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था।

उन्होंने कहा कि आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते, पीएम किसान सम्मान निधि के 21 हजार करोड़ रुपये देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। यही तो मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था, 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो आज जो आपको 21 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, उसमें से 18 हजार करोड़ रुपये बीच में ही लूट लिए जाते।

अमृत काल में हमारा देश और हमारा राज्य विकास की नई ऊंचाईयां छुएगा : साय

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का समापन

रायपुर। विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के समापन के अवसर पर कहा कि यह अमृत काल है इस अमृत काल में हमारा देश और हमारा राज्य विकास की नई ऊंचाईयां छुएगा। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को दी गई गारंटी को प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। आगामी 5 वर्षों में उनकी हर गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर बजट सत्र के सफल संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, मंत्रियों, सहित पक्ष-विपक्ष के सभी विधायकों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद आपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनके मार्गदर्शन में इस सत्र का संचालन सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने सदन के संचालन में नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने अपने अनुभवों से सत्र को नया आयाम दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी साथी अपने-अपने विभागों के माध्यम से आम नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। सत्र के संचालन में विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारियों सहित सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने कर्मठता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया। सुरक्षाकर्मियों ने अपना दायित्व बखूबी निभाया। उन्होंने विधानसभा में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को तत्परतापूर्वक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। श्री साय ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिया है, इस दिशा में हमने काम भी शुरू कर दिया है। इस सत्र की विशेष बात यह रही कि कई बार ऐसा लगा कि सत्ता पक्ष पर ही विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व आ पड़ा था।

सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए राज्य का विकास करेगी। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे और हम अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करें। आदिवासी वनवासियों, किसानों, युवाओं और महिलाओं तक उनके अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

अपने संसदीय जीवन में किसी सत्र में प्रश्नकाल का इतना बेहतर उपयोग कम देखा : रमन

विधानसभाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने अपने समापन भाषण में बताया कि बजट सत्र के कुल 20 दिवसों में लगभग 101¬13 घंटे चर्चा हुई। 16 बैठकों में 145 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस सत्र में 1337 तारांकित प्रश्न एवं 1357 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 2694 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 411 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 214 सूचनाएं पाठ्य हुई और 34 सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। इस सत्र में कुल 147 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई। शून्यकाल की 61 सूचनाएँ प्राप्त हुई जिसमें 25 सूचनाएं पाठ्य और 14 सूचनाएं अद्याक्ष्य रही। वर्तमान सत्र में 200 याचिकायें माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 130 ग्राय व 76 अग्राह्य रही। 10 अशासकीय सकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें से 05 संकल्प पाह्य हुए तथा 04 सकल्प स्वीकृत हुए एवं 1 व्यपगत हुआ। इस सत्र में विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और चर्चा उपरांत सभी पारित हुए। वित्तीय कार्यो के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 39 मिनट, वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा सहित विभागों की अनुदान मांगों पर 55 घंटे 21 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 5 घंटे चर्चा हुई। विधानसभाध्यक्ष ने कहा, अपने संसदीय जीवन में किसी सत्र में प्रश्नकाल का इतना बेहतर उपयोग कम ही देखा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस सत्र के पश्नकाल में जहां कुछ प्रश्नों के महत्व को देखते हुए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंधे गए, यही प्रश्नकाल में ही भिन्न प्रश्नों पर विभागीय जांच का आश्वासन भारसाधक मंत्री ने दिया साथ ही प्रश्नकाल में जहां शिक्षकों की पदोन्नति की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की वहीं पश्नकाल में कार्यपालिका के कुछ अधिकारियों को उनके कार्यकरण के लिए निलबित भी किया गया। साथ ही इस विधानसभा के वर्ष 2000 से लेकर आज वर्ष 2024 तक यह प्रथन बार हुआ जब पश्नकर्ता के प्रश्न पर माननीय विभागीय मंत्री ने सदन के प्रश्नकर्ता सदस्य की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कराने की घोषणा की गई हो। श्री धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न दिनांक 6 फरवरी 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुदित तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक -53) पी.डी.एस. के तहत् संचालित दुकानों की जांच विषयक पर सदन की समिति से जांच कराए जाने की सहमति शासन की ओर से दी गई। मैं समझता हूँ कि प्रश्नकाल का इससे बेहतर उपयोग का कोई दूसरा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता।

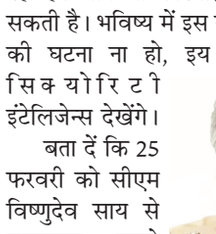

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में किए दर्शन।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक, पिस्टल लेकर सीएम के केबिन तक पहुंचा शख्स

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक लेकर खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री आवास में एक शख्स पिस्टल लेकर घुस गया। शख्स सीएम कक्ष तक पहुंचने वाला ही था, उससे पहले पुलिसकर्मियों की नजर उस शख्स के पास रखे पिस्टल पर पड़ी। मौके पर घेराबंदी कर उससे पकड़ा गया। इसके साथ ही पिस्टल जब्त कर ली गई है। मामले में अब पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।

चर्चा है कि शख्स सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात करने राज्य अतिथि गृह पहुना आया था। बता दें कि राज्य अतिथि गृह पहुना को ही अभी मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है। पिस्टल धारी शख्स वीआइपी गाड़ी से आया था। इसकी वजह से सुरक्षाकर्मियों शख्स की चेकिंग नहीं की। गाड़ी से उतरकर जैसे ही सीएम कक्ष की ओर बढ़ने लगा इस दौरान पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी और उसे पकड़ा।

सुरक्षा में बड़ी चूक पर डीजीपी का बयान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में बड़ी चूक मामले में डीजीपी अशोक जुनेजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इस मामले को देख रहे हैं। कुछ लोगों को निलंबित किया गया है। मामले की जांच चल रही है। आगे भी कार्रवाई हो सकती है। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इय पर सिक्योरिटी इंटेलिजेन्स देखेंगे।

बता दें कि 25 फरवरी को सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात करने पहुंचा एक युवक पिस्टल लेकर सीएम हाउस में घुस गया था। वह शख्स लाइसेंसी पिस्टल लेकर सीएम आवास तक आ गया था, लेकिन सीएम कक्ष के बाहर उसे रोक लिया गया। फिर उस शख्?स की पिस्?टल जब्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि यह शख्स ड्डक्क गाड़ी में आया था, जिसके चलते उनकी चेकिंग नहीं की गई थी। सीएम सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एडीजी इंटेलिजेंस ने 3 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अभी और सुरक्षा अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

प्रमुख समाचार

पीएससी घोटाला-अफसर और नेताओं के खिलाफ एफआईआर

बालोद. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के चयन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में बालोद जिले के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इंटरव्यू तक पहुंचने वाले एक युवक की शिकायत पर अर्जुंदा पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारी और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. बता दें कि इस मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला साय सरकार पहले ही ले चुकी है. छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले का मामला कांग्रेस सरकार में चर्चा में रहा. विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने इस मामले को पूरजोर तरीके से उठाया था. अब एक युवक ने थाने में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि सीजी पीएससी भर्ती परीक्षा में अनियमितता हुई है, जिसके कारण उसका चयन नहीं हो पाया है. इस मामले पर थाना अर्जुंदा में भ्रष्टाचार अधिनियम, धारा 420 सहित आईपीसी और पीआरई की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है.. वहीं अब पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित एजेंसी को मामला सौंपा जाएगा.

टीएमसी नेता शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई-ईडी स्वतंत्र

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो 5 जनवरी से फरार हैं। काफी समय तक उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका। कोर्ट ने सिर्फ विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इसलिए, फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार सीबीआई या ईडी के पास भी है। अदालत हालिया संदेशखाली अशांति से संबंधित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रही थी। सत्तारूढ़ टीएमसी के जिला परिषद नेता शाहजहाँ 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी हैं, जब वे एक कथित राशन घोटाले में छापेमारी करने गए थे। उन्हें संदेशखाली अशांति के पीछे मुख्य आरोपी भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक गांव संदेशखाली 7 फरवरी से उबाल पर है, जब गांव की महिलाएं जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न के आरोप में शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आईं।

पाकिस्तान भाजपा के लिए दुश्मन देश है: हरिप्रसाद

नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद बीके हरिप्रसाद ने बुधवार को यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि भाजपा के लिए पाकिस्तान दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी देश मानती है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राज्य भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हरिप्रसाद ने यह टिप्पणी भाजपा के उन आरोपों के जवाब में की कि मंगलवार को राज्य में कांग्रेस की राज्यसभा जीत के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। हरिप्रसाद ने विधान परिषद में कहा कि वे दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बात करते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। हमारे लिए पाकिस्तान कोई दुश्मन देश नहीं है; यह हमारा पड़ोसी देश है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हाल ही में, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया, जो लाहौर में जिन्ना की मजार पर गए और कहा कि उनके जैसा कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष नेता नहीं है। क्या तब पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं था?

तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन में चीन का झंडा

चेन्नई. तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार के एड में चीन के झंडे के इस्तेमाल से सियासत तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन बुधवार को कुलाशेखरपट्टीनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी. इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की डीएमके सरकार के पशुपालन मंत्री अनिता राधाकृष्णन ने स्थानीय अखबारों में एक ऐड जारी किया. एड में रॉकेट पर चीन का झंडा लगा था. इसे लेकर मोदी ने डीएमके पर निशाना साधा है. मोदी ने कहा कि डीएमके को भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं है. हालांकि, छ्रस्य की वरिष्ठ नेता कनिमोई ने एड में चीनी झंडे के इस्तेमाल को मानवीय भूल करार दिया है. मोदी ने तिरुनेलवेली में रैली को संबोधित करते हुए कहा- डीएमके सरकार भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. वे इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए अखबार के एड में भी चीन का स्टिकर चिपका रहे हैं. प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि डीएमके अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है. वे विज्ञापन देते हैं और इसमें भारत की अंतरिक्ष की तस्वीर भी शामिल नहीं करते हैं.

प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त

यवतमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी, 2024 को महाराष्ट्र के यवतमाल में अपनी यात्रा के दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 16 वीं किस्त जारी की। राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार PMKISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ईकेवाईसी पीएमकिसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक है। देश भर में इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का मौद्रिक इनाम मिलेगा, जिसका भुगतान प्रत्यक्ष इनाम हस्तांतरण (डीबीटी) विधि का उपयोग करके हर चार महीने में तीन समान किश्तों में उनके बैंक खातों में किया जाता है।

अपने पहले ही घोषणापत्र में भाजपा ने की थी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति को सौंपे गए अपने ज्ञापन में, भाजपा ने पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और बाद में स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए कहा। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति की स्थापना 1 सितंबर, 2023 को की गई थी।

प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी लगातार एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर देते रहे है। भाजपा लंबे समय से दावा करती रही है कि भारत के चुनाव को निष्पक्ष बनाने का सबसे बेहतर तरीका उन्हें एक साथ आयोजित करना है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने समिति से मुलाकात की। नड्डा ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि सभी त्रि-स्तरीय चुनाव तत्काल एक साथ कराना

संभव नहीं हो तो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय में स्थानीय निकाय चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ होने चाहिए अन्यथा बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से यह उद्देश्य विफल हो जाएगा। नड्डा ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के बारे में समिति को आम सहमति बनानी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे।

भाजपा 1984 से लगातार एक साथ चुनाव कराने की बात करती रही है। 1984 से यह भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा रहा है। अपने गठन के बाद पार्टी ने 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि, पार्टी को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। 1984 में भाजपा ने 1984 के चुनावों में 224 उम्मीदवार उतारे, जो इंदिरा गांधी की हत्या के दो महीने से भी कम समय के बाद हुए थे। भाजपा के घोषणापत्र में चार बुराइयों को शामिल करने का संकल्प लिया गया है जो चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को नष्ट करते है। इसमें धन शक्ति, मंत्री शक्ति, मीडिया शक्ति और बाहुबल था। इसके साथ ही चुनाव सुधार के लिए पार्टी की ओर से 11-सूत्रीय खाका प्रस्तुत किया गया था। आजादी के बाद के वर्षों में, राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट योगदान को विनियमित नहीं किया गया था।

1960 में, राजनीतिक दान पर एक सीमा लगा दी गई और 1969 में, राजनीतिक दलों और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए योगदान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1985 में, राजीव गांधी सरकार ने फिर से पार्टियों को कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति दी। भाजपा के 1989 के घोषणापत्र में 13-सूत्री चुनाव सुधार एजेंडे में कंपनी के दान पर प्रतिबंध शामिल था। पार्टी के 1984 के कुछ वादे दोहराए गए, और कुछ नए विचार पेश किए गए - अनिवार्य मतदान; दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सभी राजनीतिक और चुनावी कवरेज की निगरानी के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मीडिया का दुरुपयोग न हो; और उम्मीदवारों, उनके एजेंटों, पार्टियों और समर्थकों द्वारा चुनाव खर्च की एक सीमा तय की गई है। 1991 के अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने यू-टर्न लिया और कंपनियों द्वारा पार्टियों को चंदा देने की अनुमति देने का वादा किया। 1996 में तैयार किए गए 16 सूत्रीय चुनावी सुधार रोडमैप में, पार्टी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को खुली, आधिकारिक कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देने का वादा किया।

11-सूत्रीय खाका

- 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोट का अधिकार दें;
- मतदाताओं के लिए पहचान पत्र पेश करना;
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करें
- चुनावों की सूची प्रणाली शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करें;
- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को डाक मतपत्र का अधिकार
- हर पांच साल में राज्य और केंद्रीय चुनाव एक साथ आयोजित करें
- चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बनाएं
- चुनाव आयोग के अधिकार निकाय चुनावों तक विस्तारित करें
- चुनावों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण की व्यवस्था करें
- पार्टी खातों का सार्वजनिक रूप से ऑडिट कराएं;
- आचार संहिता को कानूनी अधिकार दें

कार्य की धीमी प्रगति पर बिफरे कलेक्टर

समीक्षा बैठक में नदारद अफसरों को नोटिस जारी करने के निर्देश

मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना के पंजीयन के संबंध में जानकारी ली और कार्ड बनाने में लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने और प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी विकासखण्डों में आयुष्मान कार्ड के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से कार्ड के पंजीयन के संबंध में जानकारी ली और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विकासखण्ड पथरिया में आयुष्मान कार्ड के नोडल और शिक्षा विभाग के सहायक परियोजना अधिकारी अजय नाथ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में भी जिला उद्योग महाप्रबंधक और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। विश्वकर्मा योजना के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जनपद पंचायत पथरिया के सीईओ को

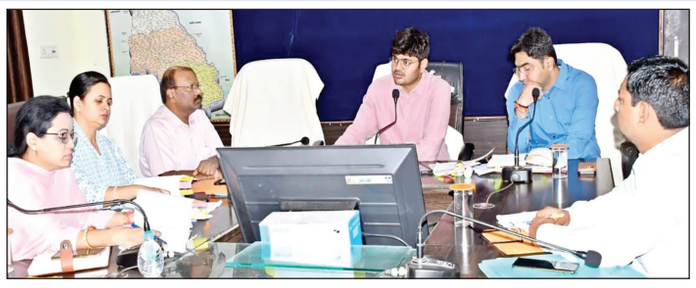

नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को शिविर लगाकर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रगति लाने तथा पंचायत और नगरीय निकाय के आधार पर रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए पूरी तत्परता से कार्य करें। कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर राहुल देव ने सिविल सर्जन को रेफरल ऑडिट करने, अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ और नर्स की व्यवस्था, चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति और अन्य संसाधनों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंध में भी जानकारी ली। लाईवलीहुड कॉलेज की सहायक परियोजना अधिकारी निखत कुरैशी ने बताया कि योजना के अंतर्गत 240 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तैयारी चल रही है। जल्द ही बैच बनाकर चिन्हांकित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने जाति प्रमाण पत्र, महतारी वंदन योजना, अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीयन, स्वच्छ भारत मिशन, धान के उठाव की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, लंबित राजस्व प्रकरणों, जनदर्शन में लंबित प्रकरणों आदि पर विस्तार से समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक प्रगति लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल, जिले में अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन सख्त है। इसके बावजूद अवैध प्लाटिंग को लेकर शिकायत प्रशासन के समक्ष लगातार आ रही है। यही वजह है कि कलेक्टर ने इसको गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने ग्राम संगवाकापा में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही पर बिजली विभाग के ठेकेदार पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर देव ने समय-सीमा की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने निर्देश दिए। उन्होंने सक्षम अधिकारी को बिना सूचना दिए बैठक में अनुपस्थित होने पर संयुक्त कलेक्टर अजीत पुजारी और सर्व शिक्षा अभियान के जिला मिशन समन्वयक ओपी कौशिक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

चार अलग-अलग हादसों से लगा लंबा जाम, घंटो बाधित रहा यातायात

गौरेला पेंड्रा मरवाही। जीपीएम जिले में आज चार सड़क हादसे हुए जिसमें दो कोयले से भरे ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हुए तो एक कोयले से भरा ट्रेलर अनियत्रित होकर खेत मे पलट गया। एक कोयले से भरा ट्रक बीच पुलिया में ट्रक के तीन टायर फट गया और पट्टा टूट जाने से तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया, वहीं एक माजदा वाहन सड़क पर खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसा। हादसे में एक ट्रेलर चालक को मामूली चोट आई है। सड़क हादसों के चलते छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली सड़क में बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित है।

जिले में आज सुबह से चार सड़क हादसे हुए है। पहला हादसा पेण्ड्रा के अमरपुर रोड स्थित अरपा उद्गम के पास हुआ जहा पर दीपिका कोयला खदान से कोयला लेकर मध्यप्रदेश के अनूपपुर स्थित जैतहरी मोजर बेयर पॉवर प्लांट जा रहा एक ट्रेलर अनियत्रित होकर खेत मे जा घुसा, हादसे में चालक को मामूली चोट आई है। दूसरा सड़क हादसा गौरेला से मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले को जोड़ने वाली मुख्यमार्ग पर हर्राटोला गांव में स्थित पुलिया पर हुआ जहां पर एक कोयले से भरा ट्रक का बीच पुलिया में तीन टायर फट गए और ट्रक का पट्टा भी टूट गया जिसके चलते ट्रक वहीं पर बैठ गया जिसके चलते हर्राटोला से गौरेला की ओर जाने वाली सड़क में तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

वहीं तीसरा हादसा गौरेला से अनूपपुर जाने वाले

मार्ग पर मेढुका गांव के पास हुआ जहां पर सड़क के किनारे खड़े ब्रेक डाउन ट्रेलर में पीछे से एक कोयले से भरा ट्रेलर जा भिड़ा हादसे में ट्रेलर का केबिन का हिस्सा पूरा तरह क्षतिग्रस्त हो गया जबकि चालक को मामूली चोट ही आई जिसके चलते मेढुका गांव से अनूपपुर को जाने वाली सड़क पर लगभग दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

चौथा हादसा वहीं मेढुका गांव के पास ही एक माजदा हादसे का शिकार हो गया जो सड़क किनारे खड़े एक कोयले से भरे ट्रेलर में पीछे से जा घुसा हादसे में चालक को मामूली चोट आई है। सड़क हादसे के चलते छत्तीसगढ़ से चलकर अनूपपुर जिले को जोड़ने वाली गौरेला वेंकटनगर अनूपपुर मार्ग पर चलने वाले वाहन चालक रात से परेशान हैं तो उत्तर प्रदेश से मध्यप्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर को जाने वाली यात्री बस भी परिवर्तित मार्ग से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही है।

थानखम्हरिया में धर्मांतरण की शिकायत पीएम आवास को चर्च बनाने का आरोप

बेमेतरा। बेमेतरा जिला के थानखम्हरिया में एक प्रधानमंत्री आवास को चर्च बनकार प्रार्थना सभा आयोजित करने और धर्मांतरण की शिकायत मिली है। बताया जा रहा है कि 5 परिवार के 25 लोग हिन्दू धर्म छोड़ इसाई धर्म अपना लिए हैं। इसकी जानकारी मिलने पर हिन्दू संगठनों, भाजपा और गौसेवकों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने थानखम्हरिया थाना में धर्मांतरण कराए जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल, पूरा मामला बेमेतरा में साजा विधानसभा क्षेत्र के थानखम्हरिया का है। यहा निवासरत 5 परिवार के 25 लोगों का धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के तहत बने मकान को चर्च बनाकर प्रार्थना सभा आयोजित करने के आरोप लगे हैं। इस बारे में सूचना मिलते ही गौसेवकों, भाजपा नेता राजा पांडेय समर्थकों के साथ थानखम्हरिया थाना पहुंचे और धर्म परिवर्तन कराने को लेकर शिकायत की है। उन्होंने संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी है।

धर्म परिवर्तन करने वाले लाभा देवार का कहना है कि उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहा था। पैसे के लिए वे भटक रहे थे। गाड़ी का किश्त भी नहीं चुका पा रहा था। उनका कहना है कि प्रभु परमेश्वर के प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उनकी सुनी और उन्हें गाड़ी के

पैसे चुकाने 50 हजार का लोन मिला। इसके तहत 10 हजार कट कर 40 हजार उन्हें मिला। अब 50 हजार लोन राशि धीरे धीरे चुका रहे हैं।

धर्मांतरण की सूचना मिलते ही बेमेतरा के गौसेवक एवं भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ थानखम्हरिया पहुंचे। उन्होंने संबंधितों से मुलाकात की और उनके साथ थानखम्हरिया थाना जाकर लिखित में धर्मांतरण के खिलाफ शिकायत किया है। फिलहाल, इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

पीएससी घोटाले में दर्ज हुआ पूर्व चेयरमैन सहित अन्य पर मामला

शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं

बालोद। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कथित घोटाले मामले को लेकर बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी सहित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धारा 420 एवं भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत यह मामला पंजीकृत किया गया है। एसपी एसआर भगत ने इसकी पुष्टि की है वहीं मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण शिकायत कर्ता का नाम अभी गुप्त रखा गया है, पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है लेकिन पूरा मामला हायर एजेंसी को सौंपा जाएगा।

पुलिस के अनुसार, बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के अभ्यर्थी ने लिखित में शिकायत की है कि वह पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 में शामिल हुआ था। वह प्रीलिम्स और मेंस पास होने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचा। उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया, लेकिन चयन नहीं हुआ, जबकि कुछ लोग इंटरव्यू से तुरंत निकल गए। उसके बाद भी उनका चयन हो गया। इसमें पीएससी

के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी का बेटा, बहू, पुत्री और अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेसी नेता, अधिकारी, कर्मचारी और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदार भी थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठे थे। उनका भी चयन हुआ है। पूरे मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अपराध पंजीबद्ध तो हो चुका है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए इसे बेहद संजीव के साथ जांच किया जा रहा है शिकायतकर्ता के परिवार और उसके नाम को गुप्त रखा गया है मामला बेहद संवेदनशील है उन्होंने बताया की धारा 420 के साथ-साथ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन इस मामले में जुट गया है।

पुलिस ने बलौदाबाजार भैंसापसरा अग्निकांड का किया पर्दाफाश

बलौदाबाजार। सिटी कोतवाली पुलिस ने बलौदाबाजार भैंसापसरा अग्निकांड का पर्दाफाश किया है। घर में आग लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी सदानंद कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपी आदतन शरारती और उपद्रवी तत्व हैं। आरोपियों ने झोपड़ी में लगे कपड़े को फाड़ने, वहां बैठने और हुल्लड़ करने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया था।

बता दें कि 24-25 फरवरी की दरम्यानी रात आरोपियों ने घर में आग लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। इस जघन्य हत्याकांड में दो लोगों की मौत हुई थी। 2 लोग जलने से गंभीर रूप से घायल हुए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया था।

बता दें कि मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि आग लगी नहीं लगाई गई है। इसके बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए नौ सदस्यीय टीम का गठन किया और गंभीर रूप से झुलसी महिला का रायपुर में बयान लिया।

महिला के बयान के बाद शक पुख्ता हुआ और पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुल्म कबुल किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को आज गिरफ्तार कर जेल भेजा।

इनकी हुई थी मौत- सोनू साहू पिता संतोष साहू उम्र 28 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार। कमला साहू पति संतोष साहू उम्र 60 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार।

आरोपियों के नाम- करन बघेल उर्फ भूखऊ पिता उमेंदी बघेल उम्र 23 वर्ष निवासी वृद्धा आश्रम के पास भैंसापसरा बलौदाबाजार। दौलत सोनवानी पिता आनंद सोनवानी उम्र 26 वर्ष निवासी दशरमा रोड भैंसापसरा बलौदाबाजार।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

खेतों में पड़ी दरारें, परेशान किसानों ने किया हंगामा

गरियाबंद। जिले के फिंगेश्वर में धान की

फसल बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। धान रोपे गए खेतों में दरार आने से किसानों में भारी आक्रोश है। कृषकों ने बुधवार सुबह खेतों में जाकर सिंचाई विभाग के उदासीन रवैये को लेकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने दो दिन के अंदर नहर में पानी छोड़ने की मांग की है। दरअसल, लंबे समय के बाद क्षेत्र के कृषकों को रबी फसल में धान की बुआई करने सिंचाई विभाग से पर्याप्त पानी दिए जाने फरमान जारी हुआ था। इससे खुश होकर ग्रामीण कृषकों ने धान का फसल लगाया था, लेकिन फिंगेश्वर के तकरीबन 300 एकड़ के रकबे में पर्याप्त सिंचाई की पानी नहीं मिलने से किसानों के मनसूबों पर पानी फिरने के साथ ही खेतों में दरारे आने से धान की खेती मरने के कगार पर हैं। इसके चलते किसान काफी परेशान है और आक्रोश हैं। अगर दो दिन के भीतर पानी नहीं मिली तो बर्बाद हो रहे फसल के लिए किसानों ने सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया।

एक लाख की इनामी महिला नक्सली का सरेंडर

दंतेवाड़ा। लाल आतंक को लगातार झटके पे

झटका लग रहा है। लोन वर्राटू (घर वापस आइये) अभियान से प्रभावित होकर एक लाख की इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित माओवादी कटेकल्याण एरिया कमेटी के पुसगुन्ना पंचायत में सक्रिय थी। बता दें कि समर्पित महिला माओवादी नक्सली बंद सप्ताह के दौरान रोड खोदकर मार्ग अवरोध करने की घटनाओं में शामिल थी। इनामी महिला माओवादी का नाम गंगा मुचाकी है। वह पुसगुन्ना पंचायत केएएमएस अध्यक्ष के पद पर काम कर रही थी। जानकारी के अनुसार लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 172 इनामी माओवादी सहित कुल 676 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्यधारा से जुड़ने का काम किया है।

दुर्ग-पुरी एक्स. का मुरीबाहाल व लोईसिंहा स्टेशन में ठहराव

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग व उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली पूरी-दुर्ग-पूरी एक्सप्रेस का मुरीबाहाल एवं लोईसिंहा स्टेशनों में ठहराव की सुविधा प्रदान की जा रही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत मुरीबाहाल एवं लोईसिंहा रेलवे स्टेशनों में 18425/18426 पूरी-दुर्ग-पूरी एक्सप्रेस का ठहराव की सुविधा 2 मार्च से प्रदान की जा रही है । यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया गया है । 1 मार्च, को पूरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18425 पूरी-दुर्ग एक्सप्रेस का लोईसिंहा रेलवे स्टेशन में 03.58 बजे पहुचकर 04.00 बजे रवाना होगी तथा 2 मार्च को दुर्ग से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18426 दुर्ग-पूरी एक्सप्रेस का लोईसिंहा रेलवे स्टेशन में 22.25 बजे पहुंचकर 22.27 बजे रवाना होगी। 1 मार्च, को पूरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18425 पूरी-दुर्ग एक्सप्रेस का मुरीबाहाल रेलवे स्टेशन में 06.10 बजे पहुंचकर 6.12 बजे रवाना होगी।

रिश्वत की मांग करने वाला सिपाही निलंबित

कोरबा। कोरबा एसपी ने कटघोरा थाने में

पदस्थ आरक्षक नंदलाल सारथी क्रमांक 880 को निलंबित कर दिया है। आरक्षक पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति से मामला रफा दफा करने के एवज में 50000 रुपये की मांग की थी। एसपी ने जन सूचना के तहत मिली शिकायत के आधार पर जब मामले की जांच की तो शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। एसपी ने आरक्षक नंदलाल सारथी को निलंबित कर दिया। एसपी द्वारा उठाए गए इस कठोर कदम से महकमें में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कटघोरा थाने में इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद अगले पक्ष पर आरक्षक के द्वारा कार्रवाई न करने की एवज में पैसे की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच की गई।

भागने की फिराक में कोर्ट की पहली मंजिल से कूदा आरोपी

कबीरधाम। कबीरधाम में मंगलवार को जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए एक आरोपी ने कोर्ट के पहले मंजिल से भागने के फिराक में कूद गया। जिसे मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने पकड़ा है। इस मामले में सिटी कोतवाली कवर्धा ने आरोपी के खिलाफ धारा 224 के तहत मामला दर्ज किया है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दुसेन नाथ योगी पिता रमेश नाथ योगी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बघर्रा पुलिस चौकी पोंडी थाना बोड़ला वर्तमान निवास गोदना रिसार्ट के सामने, वार्ड क्रमांक 17 कवर्धा को धारा 354 (क), 294, 323, 506, 10 पाक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय कबीरधाम के समक्ष पेश किया। पेश करने पर न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाने पर अभियुक्त दुसेन नाथ योगी ने पुलिसकर्मी को धक्का देकर न्यायालय परिसर से भागने लगा। आरोपी प्रथम तल (पहला मंजिल) से नीचे कूद गया। नीचे में मौजूद पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया।

इंटनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में आकर्षि ने जीता गोल्ड

■ युगांडा में बजा इंडिया का डंका

दुर्ग। इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप ने एक बार फिर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आकर्षि ने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप-2024 में गोल्ड मेडल जीता है। आकर्षि दुर्ग की रहने वाली हैं। ये प्रतियोगिता 21 से 25 फरवरी के बीच हुई थी। फाइनल मैच में आकर्षि ने हमवतन श्रुति मुंदादा को सीधे सेट्स में हराया। इससे पहले आकर्षि ने सेमीफाइनल में फ्रांस की रोजी प्लेयर और क्वॉर्टर फाइनल में कनाडा की टीजी एनजी को सीधे सेट्स में धूल चटाई थी।

युगांडा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद आकर्षि को इंग्लैंड में होने वाली ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रवेश मिला है। इस जीत के बाद आकर्षि के रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। युगांडा की प्रतियोगिता के बाद आकर्षि जर्मनी में हो रही सुपर 300 बैडमिंटन

प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये प्रतियोगिता 27 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी।

दुर्ग के कसरीडीह में रहने वाली आकर्षि ने 9 साल की उम्र में बैडमिंटन थामा। आकर्षि ने छत्तीसगढ़ के लिए जूनियर और सीनियर कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब जीते हैं। जिनमें गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में एक बार अंडर-15, दो बार अंडर-17 और एक बार अंडर-19 नेशनल चैंपियन रही है। 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ के लिए आकर्षि ने पहला गोल्ड जीता था। 16 साल की उम्र में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल हासिल किया।

वुमंस सिंगल्स में आकर्षि 2019 में देश की नंबर वन खिलाड़ी बनीं।आकर्षि की वर्ल्ड रैंकिंग 57 है। जकार्ता में 2018 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेपाल में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल किया। 2021 में सीनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब जीता था। साथ ही बहरीन में आयोजित इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के लिए ब्रांज मेडल जीता।

राशन कार्ड नवीनीकरण डेट बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वर बना बाधा

कोरबा। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण का काम चल रहा है। नवीनीकरण की तारीख फिर से बढ़ाई गई है। आम लोग अब 29 फरवरी तक अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा सकते हैं। दरअसल इस काम में सर्वर की बाधा बनी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग राशन कार्ड नवीनीकरण में पिछड़े हुए हैं। सरकारी राशन लेने के लिए कार्ड का अप टू डेट होना जरूरी है।

अकेले कोरबा जिले में नवीनीकरण के लिए लगभग एक लाख राशनकार्डधारी बचे हुए हैं। इसमें ज्यादातर राशनकार्डधारी परिवार ग्रामीण क्षेत्र के हैं। शहरी क्षेत्र में अधिकांश लोगों के पास एंड्राइड फोन है। इसके अवाला पीडीएस दुकानों में भी नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण इलाके में नेटवर्क की वजह से सर्वर में ज्यादा दिक्कतें आ रही है। इसी वजह से कई हितग्राही परेशान हैं। इसमें कोरबा, कटघोरा, पाली, करतला और पोड़ी

उपरोड़ा क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा गांव शामिल हैं।

राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरु हुई है। बीपीएल और एपीएल श्रेणी के राशन कार्डधारियों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था। इस बीच कई राशन कार्डधारी छूट गए थे। इसलिए अब आवेदन की तिथि 25 फरवरी से बढ़ाकर 29 फरवरी किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार राशन कार्डों की छंटनी और नवीनीकरण का काम समय समय पर करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वर्तमान में सभी राशन कार्डधारकों के राशन कार्ड नवीनीकरण करवाने निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए राज्य के सभी नागरिकों को 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक अपने राशन कार्डों का नवीनीकरण कराना है। छत्तीसगढ़ में करीब 76।94 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से आवेदन कर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है।

संक्षिप्त समाचार

सरकारी बैंकों में होगी 477 रिक्त पदों पर भर्ती

रायपुर। राज्य की जिला सहकारी बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कैडर के 477 रिक्त पदों में भर्ती की अनुमति राज्य शासन ने जारी कर दी है। यह जानकारी वनमंत्री केदार कश्यप ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के सवाल के जवाब में दिए। वन मंत्री ने बताया कि सरकारी संस्थाओं प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए जिला सहकारी बैंक और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कैडर के पद स्वीकृत किए गए हैं। जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित बैंक द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों से पारित प्रस्तावों के अनुसार समिति प्रबंधक के 477 रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा दी गई हैं। नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सड़क निर्माण के दौरान बुलेरो मे लगी भीषण आग, धू-धूकर जलती आई नजर

कवर्धा। जिले में एनएच 130 ए में सड़क निर्माण के काम पर लगी बुलेरो में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर गाड़ी गाड़ी धू-धूकर जल रही है। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर आसपास रहने वालों की भीड़ जुट गई है। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, दमकल की टीम को भी घटना की जानकरी दी गई है। बताया जा रहा है कि बोलेरो में शार्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी में फैल गई। घटना पोड़ी थाना क्षेत्र की है।

दादाबाड़ी में निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर 17 को

रायपुर। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एनजीओ नारायण सेवा संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याणार्थ विशाल निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन 17 मार्च को राजधानी रायपुर के जैन दादाबाड़ी परिसर में आयोजित किया गया है जहां एक हजार से अधिक लोगों की जांच की व्यवस्था की गई है। संस्थान के ट्रस्टी एवं निदेशक देवेंद्र चौबिसा, व महागंगोत्री प्रभारी रजत गौड़ ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी हादसे में या अन्य बीमारी के चलते अपना हाथ-पैर गंवा देने से अंगविहिन हुए है, उन्हें दिव्यांगता की दुःखभरी जिन्दगी से निकालने के लिए संस्थान निस्वार्थ भाव से प्रतिबद्ध है। पदमश्री अलंकृत संस्थापक कैलाश मानव की प्रेरणा से संस्थान विगंत 39 वर्षों से मानवता और दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवारत है और इसी उद्देश्य से 17 मार्च को निःशुल्क दिव्यांगता निवारण ऑपरेशन चयन एवं नारायण आर्टिफीशियल लिम्ब मैजरमेंट शिविर का आयोजन रायपुर के जैन दादाबाड़ी प्रात: 8 बजे से सांय 5 बजे तक किया गया है। शिविर में शामिल होने के लिए जरुरतमंद लोग 7023509999 में संपर्क कर अपना अग्रिम पंजीयन करा सकते है।

मां के पार्थिव शरीर को मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया कंधा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन

अग्रवाल की मां पिस्तादेवी का कल मंगलवार को निधन हो गया। आज बुधवार को निवास स्थान मौलश्री विहार से उनकी अंतिम यात्रा निकली। मां की पार्थीव शरीर को मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांधा दिया। इस दौरान उनके परिजन मौजूद थे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी की मां का पार्थिव शरीर निवास स्थान रामजी वाटिका मौलश्री विहार, रायपुर से मारवाड़ी शमशान घाट के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों को अब मिलेगा सिंचाई का पानी: साय

रायपुर। बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांवों की खेती-किसानी अब बिलकुल बदल जाएगी, यह पूरा क्षेत्र लहलहा उठेगा। यहां खेतों में सिंचाई लिफ्ट इरीग्रेशन सिस्टम से की जाएगी। इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के पहले बजट में बेलतरा क्षेत्र के खारंग जलाशय के नजदीक के 12 गांवों को लिफ्ट एरिगेशन योजना के जरिए सिंचाई का पानी देने के लिए किए गए बजट प्रावधान से इन ग्रामीणों में वर्षों पुरानी अपनी मांग के पूरा होने का विश्वास जगा है। इन उत्साहित ग्रामीणों ने राजधानी रायपुर में विधानसभा पहुंचकर आज बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की और बजट प्रावधान करने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि बेलतरा क्षेत्र के नेवसा, गिधौरी, कर्रा, जाली, टेकर, गढ़वट, अकलतरी, बाम्हू, बेलतरा, कड़री, सलखा, लिम्हा (लिम्हा जलाशय) खारंग जलाशय के नजदीक हैं, वर्षों से यहां के किसान खेतों में पानी पहुंचाने की मांग करते रहे, लेकिन इन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बजट में प्रावधान करने के बाद इन गांवों में पानी पहुंचाने के लिए नेवसा उद्वहन सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा इससे इन गांवों की 2500 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि उद्वहन सिंचाई योजना में लगभग 45 करोड़ रूपए की लागत आयेगी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री अजय चन्द्रकार, श्री भैइयालाल राजवाड़े, श्रीमती गोमती साय, श्री अनुज शर्मा, श्री गजेन्द्र यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से नई सरकार बनी है। यह किसानों की हितैषी सरकार है। हमारा देश कृषि प्रधान है। अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से आप लोग और बेहतर तरीके से खेती कर सकेंगे। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है, 3100 रूपए प्रति क्विंटल दाम भी देंगे। अभी किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। अंतर की राशि भी एकमुश्त जल्द ही दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की सरकार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई। किसानों को बिना किसी ब्याज पर ऋण की सुविधा मिली। पहले महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था और मूलधन का डेढ़ गुना चुकाना पड़ता था। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को सुविधा हुई। फसल बीमा योजना का सरलीकरण भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुना करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिया गया है। आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए किसान चैनल प्रारंभ किया गया है। पीएम सिंचाई योजना शुरू की गई। पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नगरीय निकायों में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्य पुनः स्वीकृति

रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पुनः स्वीकृति के बाद ही प्रारंभ किए जा सकेंगे। नगरीय निकायों में अधोसंरचना मद एवं राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत अप्रारंभ कार्यों को शुरू करने के लिए विभाग से पुनः मंजूरी लेनी होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय अनुशासन और शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने वित्त विभाग के निर्देश के अनुपालन में नगरीय निकायों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में प्राथमिकता वाले अप्रारंभ व निरस्त कार्यों को वर्ष 2023-24 के प्रस्ताव में पुनः शामिल कर स्वीकृति के लिए संचालनालय या राज्य शहरी विकास अभिकरण (स्डा) भेजने को कहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी परिपत्र में कहा है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने के संबंध में समय-सीमा पर निर्देश जारी किए गए हैं।

विधानसभा बजट सत्र में विधायक सुशांत के सवाल पर खेल मंत्री टंकराम ने दिया जवाब

भूपेश सरकार में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को न सम्मान मिला न नौकरी

रायपुर। विधायक लता उसेंडी की अनुपस्थिति पर सदन में उनकी ओर से भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रश्नकाल में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन और शासकीय सेवा में नियुक्ति को लेकर मामला उठाया। इस पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा, भूपेश बघेल सरकार आने के बाद पिछले सालों में न उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची प्रकाशित हुई, न कोई अलंकरण समारोह हुआ और न उन्हें नौकरी दी गई।

इस मामले में आसंदी से विधानसभा अध्यक्ष ने टिपण्णी करते हुए कहा, 5 सालों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, मंत्री ने कह दिया। ये अद्भुत है। मंत्री टंकराम वर्मा ने आगे कहा, विष्णुदेव साय सरकार खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए तमाम कदम उठा रही है। जल्द ही अलंकरण समारोह होने वाला है। आगे भी अलंकरण और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की प्रक्रिया होगी।

भाजपा विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, पिछली सरकार में वास्तविक खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलता था, पता नहीं कहां-कहां से लाते थे।

जंगल सफारी में जानवरों की मौत की जांच करेगी सेंट्रल जू अथॉरिटी

विधानसभा बजट सत्र के 17वें दिन जंगल सफारी में वन्यजीवों की मौत का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंस के सवाल पर वनमंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 2023 से जनवरी 2024 के बीच 74 वन्यजीवों की जंगल सफारी में मौत हुई है। इसके साथ मंत्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी से जांच कराने का एलान किया।

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जंगल सफारी के वन्यजीवों को आवश्यक दवाएं दी जा रही है। टीकाकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी वन्यजीव की उम्र ज्यादा हो गई थी, तो कुछ लोगों की आपसी झगड़े में मौत हुई। वन्य प्राणियों के सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है, चिकित्सा का कंपाउंडर भी है।

विधायक शेषराज हरबंस ने पूछा कि इस मामले में किसी अधिकारी और डॉक्टर के लापरवाही सामने आई है क्या? इस पर मंत्री ने सेंट्रल जू अथॉरिटी से इसकी जांच कराने का एलान किया। डॉ। राकेश वर्मा और कंपाउंडर सोनल मिश्रा के खिलाफ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि किसी बेदाग और कुशल डॉक्टर को वहां भेजे।

सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी के कब्जे की होगी उच्च स्तरीय जांच

विधानसभा के बजट सत्र के 17वें दिन ध्यानाकर्षण में रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री डॉ। शिवकुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया के कब्जे का मामला उठा। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस के बीच नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की।

विधानसभा में ध्यानाकर्षण सामुदायिक भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी के कब्जे का मामला उठाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय के अधीन है, ऐसे प्रकरणों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति के बीच राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण पढ़ा।

नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि ये सही है उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत हुई है। राजश्री समिति का सामुदायिक भवन में कब्जा है, उसे मुक्त करा लिया गया है। रंग रोगन सहित अन्य कार्यों में स्मार्ट सिटी 84.89 लाख व्यय किया गया है। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने तीन महीने में जांच कराने का एलान किया।

भाजपा ईडी-आईटी का सहारा लेकर बना रही दबाव: बैज

कांग्रेस को नहीं पड़ेगा कोई फर्क

धमतरी। लोकसभा चुनाव में बस चंद दिन रह गए हैं। जीत के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिझाने में लग गई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने तमाम दल बैठक कर रहे हैं। इन सबके बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धमतरी पहुंचकर राजीव भवन में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा ईडी और आईटी का सहारा लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस को ईडी और आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

दीपक बैज ने बैठक को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। भाजपा से ज्यादा सीट जीतने के लिए कार्यकर्ताओं में जोस भर रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाले चेहरे को टिकट दिया जाएगा। टिकट तय करने का काम आलाकमान का काम है। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में विधायक ओंकार साहू, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनके साथ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार की गई।

विकास की झलक देखने रायपुर पहुंचे आदिवासी युवा

■ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भ्रमण को लेकर कही बड़ी बात

रायपुर। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती के साथ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांवों में रहने वाले आदिवासी युवकों को प्रदेश के विकास से परिचित कराने रायपुर भ्रमण कराया जा रहा है। मन में शोषण के भाव को दूर करने के उद्देश्य से कराए जा रहे इस भ्रमण की सार्थकता आदिवासी युवाओं के कलेक्टर, डॉक्टर, पुलिस बनने की इच्छा से सिद्ध होती नजर आ रही है।

नक्सल प्रभावित अंचल से पहुंचे आदिवासी युवाओं से मुलाकात करने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इन आदिवासी युवाओं के मन में जो भ्रम फैला कर रखा गया है कि कोई शोषण करेगा, यह सब बातें गलत है। यह खत्म होना चाहिए। नक्सलियों ने खुद जितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसका कौन हिसाब देगा। आज हम बच्चो को लेकर एयरपोर्ट जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, माल जाएंगे। रात में पिक्चर हमको देखना है। बहुत सारा काम है।

उन्होंने कहा कि कि जितने साथी यहां पर आए हैं, उनमें से बहुत से कभी रायपुर नहीं आए है। वह रायपुर देखकर जाएं। उनका प्रदेश है, राजधानी है। ऐसे ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं। युवा यह देखने आए हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है, या नहीं, अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं, या नहीं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग यह कहना चाहते हैं कि सरकार उनकी सेवक है, ये अधिकारी उनके सेवक है। इसके साथ उन्होंने आदिवासी अंचल में स्थापित किए जा रहे कैंप का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिक्योरिटी का नहीं, विकास का कैंप है। विकास पहुंचना है, इसलिए कैंप है। कैंप के आसपास जितने स्थान हैं, उन सभी जगह हम हर क्षेत्र के नौजवानों को अपना प्रदेश दिखाएंगे।

गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण पर जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब ठेकेदार भी निपटा

रायपुर। लोक निर्माण विभाग ने कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य करने पर कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी ने दो अधिकारी को निलंबित कर दिया है। वहीं दो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बता दें कि लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता की ओर से 18 जनवरी को निरीक्षण और जांच में सड़क उन्नयन और नवीनीकरण का कार्य अमानक और गुणवत्ताहीन पाया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने 9 फरवरी को ठेकेदार मेसर्स एमके गुप्ता एंड कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा था। मगर ठेकेदार ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विभाग ने ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए दो वर्ष के लिए उसका पंजीयन निरस्त कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर मामले में दो अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पीडब्ल्यूडी के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता की ओर से चोटिया-चिरमिरी मार्ग के 10 किमी लंबाई के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.30 किमी) के निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल की जांच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम पाई गई। साथ ही किए गए कार्य की डेंसिटी (घनत्व) भी कम पाई गई। कार्य अमानक स्तर का पाया गया। सड़क के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए नियुक्त ठेकेदार मेसर्स एमके गुप्ता एण्ड कंपनी, अ वर्ग ठेकेदार, कोरबा की ओर से गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही मार्ग का डामरीकरण कर गुणवत्ताविहीन कार्य कराया गया है। इससे मार्ग में जगह-जगह गड्ढा हो गया है। अमानक और गुणवत्ताहीन कार्य के लिए मुख्य अभियंता की ओर से ठेकेदार को कम से कम दो साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा की गई थी।

ठेकेदार की ओर से किया गया कार्य शासन और लोक हित के विपरीत होने के कारण प्रमुख अभियंता कार्यालय ने ठेकेदार मेसर्स एमके गुप्ता एण्ड कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा था। इसके बावजूद ठेकेदार ने आज तक जवाब नहीं दिया है। इस कारण प्रमुख अभियंता ने दो वर्ष के लिए ठेकेदार का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की है।

राजिम कुंभ कल्प को लेकर सियासत, कांग्रेस-भाजपा के बीच बयानबाजी

■ लेकिन नाम को लेकर इतिहासकार की राय जुदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम में कुंभ को लेकर राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने प्रदेश के राजिम में अर्धकुंभ कराने का फैसला लिया था। इसे बीजेपी सरकार ने राजिम कुंभ नाम दिया ।बीजेपी सरकार के आयोजन में देश के साधु, संत और महात्मा शामिल होते थे ।लेकिन जब प्रदेश में 2018 में कांग्रेस सरकार आई तो राजिम कुंभ का नाम बदलने की तैयारी शुरु हुई ।कांग्रेस सरकार ने राजिम कुंभ का नाम बदला और इसे राजिम पुन्नी मेला का नाम दिया ।वहीं अब जब कांग्रेस सत्ता से गई तो एक बार फिर राजिम पुन्नी को नया नाम दिया गया ।लेकिन बीजेपी ने फिर से राजिम कुंभ कल्प को शुरु किया है ।जिसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं।

इस बारे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों की भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम राजिम कुंभ है ।लेकिन कांग्रेस ने राजिम कुंभ का नाम बदलकर अपनी सरकार की मोहर लगाने के लिए पुन्नी मेला कर दिया। राजिम कुंभ बीजेपी सरकार ने शुरू किया था। इसलिए उसे बंद कर कांग्रेस सरकार ने पुन्नी मेला शुरु किया। हमने किसी के कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया ।लेकिन पुराने राजिम कुंभ को दोबारा शुरु किया ।संजय श्रीवास्तव के मुताबिक धर्म के नाम पर कांग्रेस हमेशा से विरोध की भावना प्रकट करती है। चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो या कोई और बात। हम मन से आस्था के साथ धार्मिक चीजों को सामने लाते हैं।

भाजपा प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव ने कहा कांग्रेस केवल वोट बैंक के आधार पर धर्म को सामने लेकर आती है। यह मूल अंतर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर में है। राजिम कुंभ शुरु हुआ है। लोगों में खुशी है। लाखों की संख्या में लोग राजिम पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। पुण्य ले रहे हैं ।ये बीजेपी का अच्छा कदम है।

वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। धनंजय सिंह ठाकुर के मुताबिक बीजेपी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, तीज त्यौहार, बोली भाखा, रहन-सहन, खानपान पीड़ा क्यों है। जब भी बीजेपी सरकार में आती है, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं से छेड़छाड़ करती है। उसके मूल स्वरूप को बदल देती है। उनके नाम में परिवर्तन कर देती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है राज्य की संस्कृति को बचाए ।लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी उल्टा काम करके संस्कृति को ही नष्ट कर रही है।

राजिम के त्रिवेणी संगम में माघी पुन्नी मेला का आयोजन वर्षों से होते आ रहा है। इसकी एक अपनी मर्यादा, पहचान और श्रद्धा है। राष्ट में जो चार बड़े महाकुंभ होते हैं, उसकी एक पौराणिक मान्यता है, जिसके प्रति पूरे देशवासियों की श्रद्धा है। लेकिन बीजेपी उस महाकुंभ को भी चैलेंज करने का काम कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विपरीत काम किया है। यह बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यजनक हैं। राजिम कुंभ के स्थान पर यदि पुन्नी मेला का आयोजन होता है,तो इससे बीजेपी को क्या परेशानी थी।

राजिम में पुन्नी मेला और कुंभ के प्रमाण को लेकर इतिहासकारों का अपना पक्ष है। इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र के मुताबिक सैकड़ों साल से कलचुरी काल, मराठा काल से राजिम में मेला लगता आ रहा है। राजिम में मेले का एतिहासिक और पौराणिक प्रमाण भी मिला है। पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला गंगा कहा गया है। राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन पिछली सरकार के पहले कई वर्षों तक चला आ रहा था। इतिहासकार रमेंद्रनाथ मिश्र ने कहा भारतीय इतिहास में देखा जाए तो 12 वर्ष में एक बार अलग-अलग जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। राजिम कुंभ की बात की जाए तो जिसे फिर से चालू किया गया है। वह %राजिम कुंभ कल्प% है। इनको कुंभ ही नहीं माना जा रहा है, उसके समकक्ष माना जा रहा है। इसने किसी भी व्यक्ति और विचारधारा के लोग आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतिहासकार की माने तो छत्तीसगढ़ में मेले का आयोजन पुरातनकाल से होता आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने राजिम में कुंभ का आयोजन कराया था ।लेकिन प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनीं तो राजिम कुंभ को पुन्नी मेला नाम दिया गया। इसका आयोजन भी भव्य तरीके से किया गया ।लेकिन अब जब प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, एक बार फिर पुन्नी मेला का नाम बदलकर राजिम कुंभ कल्प किया गया। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति कब तक होती है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बलौदाबाजार (छ.ग.)

निविदा क्रमांक 107/ले.शा./का.अ./ लो.स्वा.यां. / खण्ड, बलौदाबाजार, दिनांक 16.02.2024

मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना

'प्रपत्र- ए' में लोक निमार्ण विभाग छत्तीसगढ़ में एकीकृत पंजीयन ई-रजिस्ट्रेशन की श्रेणी 'डी' एवं उच्च में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण:-

क्रमांक	निविदा क्रमांक	ग्रुप	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि
1	107 / 16.02.2024	ग्रुप-1	सिमगा विकासखंण्डं के ग्राम दामाखेडा संत समागम मेला स्थाल पर अस्थाई पेयजल व्यवस्था	6.40 लाख	5000 रू.
		ग्रुप-2	ग्राम खंडवा में दशहरा स्थल पर पेयजल व्यवस्था हेतु पाईप लाईन विस्तार कार्य	3.39 लाख	4000 रू.

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा संबंधी अन्य जानकारियाँ कार्यालयीन समय में खण्ड कार्यालय बलौदाबाजार के सूचना पटल पर देखी जा सकती है तथा आवेदन की अंतिम तिथि 01.03.2024 है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बलौदाबाजार-भादापारा (छ.ग.)

जी-08117/4

भाजपा को अपनी जीत का भरोसा

प्रभु चावला

दिमागी खेल से चुनाव का फैसला होता, तो भाजपा अब तक जीत चुकी होती और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बन चुके होते। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव बाकी हैं, जिनमें 90 करोड़ से अधिक लोग मतदान करेंगे। लेकिन मोदी के लिए ऐसा लगता है कि यही नतीजा होगा। यह कहकर कि उनकी पार्टी और सहयोगी दल 400 सीटें जीतेंगे, मोदी ने संख्या के आख्यान को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया है कि समूची चुनावी चर्चा उनकी संख्या के इर्द-गिर्द हो, न कि शासन और कामकाज पर। अपनी संभावित जीत का बड़े अंतर का माहौल बनाकर उन्होंने विरोधियों को निरुत्साहित और अपने समर्थकों को उत्साहित करने की कोशिश की है। अगर भाजपा 370 सीट जीतती है, तो पिछली बार जीती गयीं कांग्रेस की 54 सीटें आधी रह जायेंगी। संभवत: अपनी ऐतिहासिक तीसरी जीत पर आश्वस्त होकर उन्होंने अगले माह के शुरू में कैबिनेट की बैठक बुलायी है, जिसमें उनकी अगली सरकार के पहले सौ दिनों की योजना पर चर्चा होगी। आंकड़ों को लेकर उनके भरोसे पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक सत्तारूढ़ दल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों की कुल 116 सीटों में 106 भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास हैं। अनेक राजनीतिक उतार-चढ़ाव के कारण बिहार और महाराष्ट्र का महत्व बढ़ गया है। बिहार में भाजपा और जद(यू) गठबंधन ने 2019 में 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर नीतीश कुमार एनडीए से नाता छोड़ लालू प्रसाद के राजद के साथ कुछ समय के लिए चले गये थे और फिर भाजपा के साथ वापस आ गये। इससे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता और पिछड़ी जातियों के लिए उनकी प्रतिबद्धता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। साल 2019 में भाजपा ने अपनी सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी और जद(यू) एक सीट हारी थी तथा 16 सीटें जीती थीं। उनके अन्य सहयोगी एलजेपी ने भी अपनी सभी छह सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं और क्या चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी भी अपनी सभी सीटें जीत सकती है। इस पर चर्चा जारी है, पर भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन अगर जद(यू) और एलजेपी ने कुछ सीटें गंवा दी तो? विशेषज्ञों ने इसका एक उत्तर खोज निकाला है। उनका कहना है कि भाजपा का स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो वह ऐसे नुकसान की भरपाई कर देगी। इसका मतलब यह है कि भाजपा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पर यह मुख्यमंत्री और चिराग पासवान पर निर्भर करेगा। ऐसे ही संदेह महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर भी व्यक्त किये गये हैं। भाजपा और अविभाजित शिव सेना ने महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें जीती थीं। अब, जब शिव सेना और एनसीपी में विभाजन हो गया है और नेताओं ने पाला बदला है, तो परिणाम को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिव सेना 18 सीटें जीत सकती है या क्या भाजपा अधिक सीटों पर लड़ेगी ताकि एनडीए की संख्या ऊपर जाये? कर्नाटक में कांग्रेस आगे दिख रही है क्योंकि हाल में उसने विधानसभा जीता है और भाजपा राज्य इकाई में अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। साल 2019 में 10 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की 92 में से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पायी थी। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और तमिलनाडु की 39 सीटें शामिल हैं। पार्टी के अपने शोध के अनुसार, भाजपा देश के लगभग 175 क्षेत्रों में शायद ही कभी जीती है। इनमें तीन दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर और पश्चिम का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। चुनाव न लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ राज्यसभा सांसदों के साथ पिछले एक साल से इन क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं और विकसित भारत के मोदी मंत्र का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने अपने को यह भरोसा दिलाया है कि वह इन राज्यों से कम से कम सौ सीटें पहली बार जीत सकती है। शीर्ष नेतृत्व ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल में बड़ी जीत के साथ 370 सीटों का उसका लक्ष्य पूरा होगा।

लोकतंत्र के लिए सौदा बनती राजनीति

अनिल तिवारी

जैसे-जैसे चुनावी खर्च बढ़ा है, राजनीतिक पार्टियों की हैसियत भी बढ़ते हुए हजारों करोड़ की हो गई है। चुनावी बांड के जरिए भारतीय लोकतंत्र के गले में पड़ी पूंजी की फांस को लेकर देश की सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर लगी है। मालूम हो कि बीते 15 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले चुनावी चंदे की जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने बैंक को कहा है कि वह तीन सप्ताह के भीतर सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराए और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। वर्ष 2022-23 के लिए आंकड़ा मोटा-मोटी 16 सौ करोड़ रुपए का है, जो राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में मिला है। देखना यह है कि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर कितना पैसा दर्शाता है और सभी पैसा देने वालों के नाम उजागर करता है या नहीं?

साफ सुथरे संसाधन के साथ चुनाव लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य माना गया है। लेकिन बाजार की दखलंदाजी के कारण चुनाव लगातार मंहगे होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से अधिक भरोसा पेशेवर लोगों पर कर रहे हैं। पार्टियां अपने चरित्र और कार्यशैली को पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर के रूप में बदल रही हैं। टेक कंपनियां भी इस मौके को खूब भुना रही हैं और राजनीतिक दलों को अपना क्लाइंट बनाकर मोटी कमाई कर रही हैं। इस संकट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही भांप लिया था। वर्ष 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉर्पोरेट से चुनावी चंदे के प्रचलन को खत्म करने के लिए लोकसभा में निजी सदस्य बिल पेश किया था। तर्क दिया गया था कि संभव है कि सभी पक्षों को कॉर्पोरेट से चंदा लेना मंजूर न हो, इसलिए उनकी सहमति लिए बिना कॉर्पोरेट से चंदा लेने को मंजूरी देना अनैतिक होगा।

वाजपेयी का कहना था कि ऐसे चंदों से केवल कॉर्पोरेट के हित सधेंगे। जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिल का स्वागत किया वहीं तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस पार्टी ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया। उसके बाद ऐसा बिल कभी पेश नहीं हुआ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 बी के तहत राजनीतिक पार्टियां विदेशी स्रोतों को छोड़कर किसी से भी चंदा ले सकती हैं। इससे दो निष्कर्ष निकालते हैं, पहला- धन में राजनीतिक एजेंडा को प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरा, विदेशी चंदा चुनावी शुचिता को खंडित करता है। यह दोनों बातें उस व्यक्ति, गैर मतदाता पर भी बराबर लागू होती है जिसका चुनाव प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। विदेशी स्रोत से चंदे के साथ जैसी चुनौतियां जुड़ी है, वैसी ही चिंताएं कॉर्पोरेट से मिलने वाले चंदे के साथ भी जुड़ी होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां विदेशी चंदा न्यायिक परिधि से बाहर है तो दूसरा यानी कॉर्पोरेट चुनाव में प्रतिभागी न होने से चुनावी प्रक्रिया के लिए बाहरी तत्व हैं। लेकिन पार्टीगत हितों के चलते इस कानून को ठोस नहीं बनाया गया।

वाजपेयी ने अपने बिल में कॉर्पोरेट बनाम आम नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जिक्र किया था। आमतौर पर कॉर्पोरेट ग्रुप अपने सदस्यों, जिन्हें व्यापार की स्वतंत्रता है, के आर्थिक हितों को साधने वाले संगठन होते हैं। इसलिए उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य कारोबारी स्वतंत्रता से होता है। यकीनन यह स्वतंत्रता व्यावसायिक उद्देश्य वाली होती है। दूसरी तरफ नागरिकों के पास अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता है, जो राजनीतिक क्षेत्र तक विस्तार ले लेती है। चूंकि कॉर्पोरेट मतदाताओं की भांति लोकतंत्र में प्रतिभागी नहीं होते, इसलिए उनका राजनीतिक भाषण और अभिव्यक्ति के लिए कोई दावा नहीं होता। इसीलिए जहां नागरिक मतदाता अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते हैं, वहीं कॉरपोरेट को किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने से बचना चाहिए। वाजपेयी जी ने सदन में जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था उसका मूल मकसद चुनाव सुधार से जुड़ा था।

अदालत के हालिया निर्णय के बाद चुनाव सुधार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है तो उसके कारणों में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता भी शामिल है। भारत में समय-समय पर इस प्रक्रिया की कमियों को दूर करने के लिए सुधार किया जाता रहा है। टीएन शेषन जैसे निर्वाचन आयुक्तों ने अपने कुछ कड़े निर्णय से बड़े सुधार किये और ख्याति प्राप्त की। उस दौर में धनबल के साथ बाहुबल का प्रयोग कर पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव को प्रभावित किया जाता रहा। तब बूथ कैपचरिंग जैसे हथकंडे अपनाने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचने लगे थे, लेकिन उनके समर्थकों पर जब शेषन और के जे राव की शक्ति का डंडा चला था, तब बाहुबली जड़ मूल से खत्म हो गये।

चुनाव सुधार के लिए शेषन के समय में गठित दिनेश गोस्वामी समिति, राजनीति के अपराधीकरण पर बोहरा समिति आदि की सिफारिशों पर ढेर सारा सुधार किया गया, जिसका सकारात्मक प्रभाव सीधे रूप से दिखाई पड़ता है। लेकिन अब तक के तमाम सुधारों के बावजूद धन बल के प्रयोग की स्थिति इतनी भयावह बन चुकी है कि छोटे से छोटे चुनाव में भी प्रत्याशियों द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। पिछले कुछ चुनाव आंकड़ों को देखें तो कानून सम्मत और असल खर्च के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे मे अगर खर्चे ज्यादा है, तो बगैर चंदा, बगैर सहयोग के कोई प्रत्याशी या कोई राजनीतिक दल चुनाव में कैसे हिस्सा ले सकता है?

यही कारण है कि वास्तविक राजनीतिक अर्थों में किसी भी पार्टी को चंदा संबंधी कानून में सुधार से कोई फायदा नजर नहीं आता। सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ मुख्य विपक्षी पार्टी तक को उम्मीद होती है कि जब वह सत्ता में आएगी तो इस सहूलियत से लाभान्वित हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनावी चंदा संबंधी मामले को निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाए। राजनीतिक दलों को निष्पक्ष और पारदर्शिता से चंदा मुहैया कराने के लिए जरूरी है कि बेहिसाबी पैसे और कॉरपोरेट और गैर मतदाता द्वारा राजनीतिक दलों को सीधे चंदा दिए जाने का नियमन हो। इस क्रम में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सरकार की तरफ से धन मुहैया कराना भी कारगर विकल्प हो सकता है। इस तरह की योजना प्रत्यक्ष करों पर एक प्रतिशत का उपकार लगाकर कारगर बनाई जा सकती है। निर्वाचन आयोग एक राष्ट्रीय निर्वाचन कोष बना सकता है, जिसमें उपकार से संग्रहित धन जमा किए जाए।

उपकर प्रगतिशील होने के कारण गरीब उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं से सीधे चंदा लेने की छूट हो। जो मतदाता नहीं है वह अपना योगदान तटस्थ रूप से निर्वाचन कोष में दे सकते हैं। कॉर्पोरेट द्वारा अगर इस कोष में पैसा दिया जाता है तो उससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि चुनाव में लोगों की निष्ठा में इजाफा होगा। राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में आने के बाद अधिक से अधिक समावेशी एजेंडा को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित होंगी। मतदाताओं का महत्व बढ़ेगा और तभी लोकतंत्र वास्तव में लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बन सकेगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-18)

गतांक से आगे...

बाल्यकाल में गुरु से, माता-पिता से, लोगों से, आयु में बड़े लड़कों से एवं अन्य दूसरे लोगों से भी भय लगता है, अत: यह बाल्यावस्था भय का ही घर है। युवावस्था के आने पर अपने ही चित्त रूपी गुफा में निवास करने वाले, भिन्न-भिन्न तरह के भ्रमों में फँसाने वाले इस काम रूपी पिशाच से बलपूर्वक विवश होकर व्यक्ति पराजय को प्राप्त हो जाता है। वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर उन्मत्त की भाँति काँपते हुए व्यक्ति को देखकर दास, पुत्र-पुत्रियाँ, स्त्रियाँ एवं बन्धु-बान्धव भी हँसी करते हैं।

वृद्धावस्था में शरीर असमर्थ हो जाने पर इच्छा-आकांक्षाएँ अत्यधिक बढ़ जाती हैं। यह वृद्धावस्था हृदय में दाह प्रदान करने वाली सारी आपत्तियों की प्रिय सहेली है।

इस नश्वर जगत् में रहने वाले सांसारिक प्राणी जिस सुख की भावना करते हैं, आखिर वह कहाँ है? काल आयु को तृण के सदृश काटता ही जा रहा है। वह काल छोटे से तृण एवं रज: कण को महेन्द्र एवं स्वर्णमय सुमेरु जैसे विशाल पर्वतों को भी सरसों के समान बना देने में समर्थ है। यह सभी का संहार करने में सक्षम तथा अपनी उदरपूर्ति के लिए सभी को आत्मसात् करने को उद्यत है। इस काल के द्वारा तीनों लोक आक्रान्त हैं।

यंत्रवत् चञ्चल अङ्गरूपी पिंजड़े में मांस की पुतली की भाँति, स्नायु एवं हड्डियों की ग्रन्थि से बनी हुई इस स्त्रीदेह में ऐसी कौन सी वस्तु है, जो शोभनीय कही जा सकती है?

आँखों में स्थित त्वचा, मांस, रक्त एवं अश्रु आदि इन सबको अलग-अलग करके अवलोकन करो; इनमें कौन सी वस्तु आकर्षक प्रतीत होती है? यदि कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं, तो फिर व्यर्थ में मोह करने से क्या लाभ है?

क्रमश: ...

इंदिरा गांधी के कट्टर विरोधी थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई

रेनू तिवारी

भारत के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात के भदेली गांव में 29 फरवरी, 1896 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जबकि 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। कांग्रेस के बेहद करीबी लोगों में से एक मोरारजी देसाई को पार्टी छोड़ने के बाद 81 वर्ष की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था और 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।

1975 में जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था उसके बाद इंदिरा गांधी का विरोध पूरे देश में हो रहा था। आपातकाल में जिस तरह का वातावरण था उसे लेकर इंदिरा गांधी को लोग फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इंदिरा गांधी के विरोध के बाद जब जनता पार्टी को लोगों का समर्थन मिला और इस दौरान राजनीति के नये भविष्य के रूप में कई सितारे उभरे जिसमें से एक थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई लंबे समय से कांग्रेस के विरोधी थे। जनता पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोरारजी रणछोड़जी देसाई भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने 1977 और 1979 के बीच भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में जनता पार्टी द्वारा गठित सरकार का नेतृत्व किया। मोरारजी देसाई उस समय के इकलौते ऐसे नेता थे जो कई मंचों से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके थे और वह कभी इस पर बोलने से बचते भी नहीं थे।

मोरारजी देसाई एक स्वाधीनता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। राजनीति में अपने लंबे कॅरियर के दौरान, उन्होंने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानंमत्री पद पर किसे काबिज किया जाए। इस पर चर्चा तेज हो गए थी लेकिन फिर मोरारजी देसाई पर आकर चर्चा समाप्त हुई और उन्हें मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था।

मोरारजी देसाई 1969 तक इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1969 के विभाजन के दौरान उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस (ओ) में शामिल हो गए। 1977 में विवादास्पद आपातकाल हटाए जाने के बाद, विपक्ष के राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी की छत्रछाया में कांग्रेस के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी और 1977 का चुनाव जीता। देसाई प्रधान मंत्री चुने गए, और भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधान मंत्री बने। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर मोरारजी देसाई ने अपनी शांति सक्रियता के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और दो प्रतिद्वंद्वी दक्षिण एशियाई राज्यों, पाकिस्तान और भारत के बीच शांति शुरू करने के प्रयास किए। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद, देसाई ने चीन और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल करने में मदद की, और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध जैसे सशस्त्र संघर्ष से बचने की कसम खाई। उन्हें 19 मई 1990 को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया।

ट्रंप और पुतिन बढ़ा सकते हैं यूरोप की मुश्किलें

रहीस सिंह

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप साउथ कैरोलाइना में निकी हेली को उनके गृह राज्य में पराजित कर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी कमोबेश पक्की कर चुके हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ देखते समय ट्रंप की तरफ देखना जरूरी हो जाता है। इसकी कई वजहें हैं। पहली, उनका कार्यकाल अनिश्चित अमेरिकी विदेश नीति का काल रहा। दूसरी, कैपिटल हिल जैसी घटना अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद पहली बार घटी, जिसमें अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्य कुचले जाते दिखे। तीसरी, वह लगातार कह रहे हैं कि वही एक मात्र उम्मीदवार हैं, जो दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध की ओर जाने से रोक सकते हैं। चौथी, उन्होंने यह भी कहा कि 'जो नैटो देश अपने बिल नहीं भरते, उन पर मनचाही कार्रवाई करने के लिए वह रूस को प्रोत्साहित करेंगे।'

क्या ये बातें अमेरिका के सीधी और स्पष्ट रेखा पर चलने का संकेत देती हैं? एक बात और, नैटो देशों पर ट्रंप का ऐसा बयान उत्तरी अटलांटिक ब्लॉक की सुरक्षा की दृढ़ता का परिचायक है या नई कमजोरी का संकेत? वास्तव में ऐसी अनिश्चितता दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध से बचाएगी या उसी दिशा में धकेल देगी? ऐसी टिप्पणियों के बाद भी ट्रंप का रिपब्लिकन कैंडिडेट्स में आगे होना आश्चर्य में डालता है। पता नहीं यह 'पोस्ट ट्रुथ' का कमाल है या राष्ट्रपति जो बाइडन की शिथिलता और घटती लोकप्रिता का।

करीब 17 वर्ष पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था ङ्क नैटो शांति नहीं, उकसावे की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आज ये बातें इसलिए प्रासंगिक लगती हैं क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्त्राइल-गाजा संघर्ष के चलते दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध के कगार पर न भी हो तो शीतयुद्ध के भंवर में अवश्य दिख रही है। ध्यान रहे, रूस-यूक्रेन युद्ध के दो वर्षों में किसी भी दिशा से शांति के वास्तविक प्रयास नहीं दिखे।

यूरोप इसके लिए मॉस्को को कठघरे में खड़ा करता है। उसका तर्क है कि रूस की कार्यवाही से यूरोप की सामरिक स्थिति बदली है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ही रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए और यूक्रेन को हर तरह की मदद दी गई है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। हकीकत यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पूर्वी यूरोप की ओर नैटो का विस्तार करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी से यूरोप की सामरिक स्थिति बदली, जिसे रूस ने अपने अस्तित्व पर गहरा रहे संकट के रूप में देखा।

दरअसल, जब बर्लिन की दीवार टूटी और जर्मनी का एकीकरण हुआ, तब सोवियत संघ को भरोसा दिलाया गया था कि यह डिवेलपमेंट सोवियत संघ पर सामरिक दबाव का कारण नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नैटो न केवल बना रहा बल्कि उसका पांच बार विस्तार कर सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस को भू-राजनीतिक तौर पर घेरने की रणनीति अपनाई गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी ब्लॉक के देशों को यह अच्छी तरह से मालूम था कि रूस सैन्य खर्च में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएगा।

इसके खिलाफ रूस की पहली प्रतिक्रिया 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के रूप में आई। इससे उसने सेवास्तेपोल को बचाया और 'ब्लैक सी' में स्थिति मजबूत कर ली। पश्चिमी ब्लॉक के लिए यह एक बड़ा झटका था क्योंकि इसने अचानक पूर्वी यूरोप सहित यूरेशिया के अंदर के रणनीतिक समीकरण को बदल दिया। यही नहीं, क्रेमलिन इसके जरिए एक नया संदेश देने में कामयाब हो गया।

यह पश्चिमी ब्लॉक के लिए अपनी समीक्षा और अमेरिका के लिए अपने पुनर्मूल्यांकन का समय था। रूस-यूक्रेन युद्ध के दो वर्ष पूरे होने के बाद भी अमेरिका सहित पश्चिमी ब्लॉक ऐसा कर पाया, यह कहना मुश्किल है। आज जब ट्रंप नैटो देशों को धमकी दे रहे हैं कि वह उनके खिलाफ रूस को उकसाएंगे, तब क्या इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि 1991 के बाद नैटो को बनाए रखने का उद्देश्य क्या था।

तो क्या वर्ष 1991 सोवियत संघ के पतन के साथ-साथ नए शीत युद्ध की शुरुआत और भावी युद्धों के लिए 'लाइन ऑफ डिमार्केशन' का वर्ष था? यदि नहीं, तो सोवियत संघ के पतन से लेकर 2024 तक तक दुनिया जिन संघर्षों से गुजरी, वे नैटो के होते हुए कैसे संभव हो गए? नैटो के रहते मध्य-पूर्व में पहले तानाशाहों और फिर आतंकवाद का उदय क्यों हुआ? और यह भी कि नैटो के होते हुए एंग्लोस्फेयर इंटेलिजेंस अलायंस (आई फाइव), ऑकस आदि की आवश्यकता क्यों पड़ी?

बहरहाल इस समय पुतिन यूरोप को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। यह शायद रूसी अर्थव्यवस्था के जी7 की तुलना में मजबूत होने का ही एक संकेत है। फरवरी के पहले सप्ताह में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी ब्लॉक जब प्रतिबंधों पर दांव लगाए हुए थे, तब रूस अपनी अर्थव्यवस्था को 'मॉबिलाइज्ड वॉर इकॉनमी' में बदल रहा था? यदि ऐसा है तो पश्चिमी ब्लॉक को अपनी रक्षापंक्ति और मजबूत करने की जरूरत है। विशेषकर तब जब अमेरिका बहुत हद तक डगमगाता हुआ ही नहीं ट्रंप के नेतृत्व की ओर सरकता दिख रहा है। जाहिर है, आज ट्रंप की लोकप्रियता और पुतिन की आक्रामकता से जुड़े तमाम पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं।

आज का इतिहास

1744 फ़्रांस के प्राकृतिक दर्शनशास्त्री जॉन थियोफिलस डेजाग्युएलिये का निधन हुआ। वे रॉयल सोसायटी आफ लंदन के सदस्य थे।
1752 अलबंगपाया, ऊपरी बर्मा में एक ग्राम प्रधान, ने कोनबंग राजवंश की स्थापना की; अपनी मृत्यु के समय तक, उन्होंने म्यांमार के सभी लोगों को एकजुट कर दिया था, और फ्रांसीसी और ब्रिटिशों को बाहर निकाल दिया था।
1768 पोलिश रईसों के एक समूह ने रूसी संघ के प्रभाव और राजा स्टेनिस के खिलाफ पोलिश-लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल की आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बार परिसंघ की स्थापना की
1792 भ्रूणविज्ञानी कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर का जन्म हुआ, जिन्होंने सन् 1827 में स्तनधारियों के अण्डाणु की खोज की। उन्होने ऊतकों की परतों से भ्रूण के विकास के बारे में बताया।
1840 आयरिश -अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन फ़िलिप हॉलैण्ड का जन्म हुआ। जिन्हें आधुनिक पनडुब्बी का जनक माना जाता है। सन् 1898 में उन्होने हॉलैण्ड नामक पानी के अंदर संचालित पहला अमेरिकी जलयान बनाया।
1860 हरमन होल्लेरिथ ने सारणी मशीन का आविष्कार किया था।
1928 अमेरिकी कवयित्री , लेखिका और पुस्तकालय संचालिका इनका डोन्ना कूलब्रिद का निधन हुआ। जो अमेरिका की पहली सरकारी कवयित्री थीं।
1936 नेचर पत्रिका ने नील्स बोर के बाउल आफ बॉल्स के बारे में छापा।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के प्रशांत युद्ध के दौरान एडमिरल्टी द्वीप अभियान शुरू हुआ जब अमेरिकी बलों ने एडमिरल्टी द्वीप समूह के तीसरे सबसे बड़े लॉस नेग्रोस द्वीप पर हमला किया।
1960 मोरक्को के सबसे घातक भूकंप ने अगाडिर शहर पर हमला किया, जिसमें कम से कम 12, 000 लोग मारे गए।
1960 मोरक्को के दक्षिणी शहर अगादीर में आए भीषण भूकंप में हज़ारों लोगों की मौत हो गयी। इस भूकंप की तीव्रता 6.7 थी।
1964 अमेरिकी गुप्त रूप से विकसित जेट फाइटर ए -11 का अंत लिंडन बैनेस जॉनसन ने किया।
1968 नागरिक विकारों (केनर कॉम) पर नस्लवाद के खिलाफ रिपोर्ट और राष्ट्रीय सलाहकार आयोग द्वारा अश्वेतों को सहायता देने की मांग की गई थी।
1972 Dita दाढ़ी (IIT) ज्ञापन का खुलासा जैक एंडरसन द्वारा किया गया था, यह दर्शाता है कि रिपब्लिकन पार्टी में .400000 के योगदान के लिए अविश्वास के आरोपों को हटा दिया गया था।
1984 कनाडा के प्रधान मंत्री पियरे इलियट ट्रूडो ने घोषणा की कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।
1984 कैनेडियन प्रधान मंत्री, पियरे ट्रूडो ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की
1988 टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत में, मार्क ग्रेटबैच द्वारा 107 रन बनाए गए थे जब वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे
1992 LPGA केम्पर गोल्फ ओपन चैंपियनशिप डॉन कोए ने जीती।
1996 क्रिकेट विश्व कप 1996 में, केन्या ने वेस्टइंडीज को 93 रनों में सभी विकेट लेकर हराया।
1996 चार साल तक लगातार गोलीबारी और हमलों के बाद बोसनिया की राजधानी सरायेवो की घेराबंदी ख़त्म हो गयी।
2004 16 वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर समारोह में सीन पेन और चार्लीज़ थेरॉन ने लीड एक्टिंग अवार्ड जीते, जिसमें बिली क्रिस्टल्स होस्ट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द किंग ऑफ द रिटर्न जैसे सभी ग्यारह नामांकन शामिल हैं।

बंगाल में अत्याचार और भ्रष्टाचार के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं

योगेंद्र योगी

पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के तौर-तरीकों से यही लगता है यह भारत का नहीं बल्कि किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा है। देश का यह एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां संविधान के अनुसार शासन करने की जद्दोजहद जारी है। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार की मनमर्जी ने इस प्रदेश के हालात बिगाड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल ऐसे प्रदेश की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जहां सरकार समर्थित लोगों पर भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। घोटालों, चुनावी हिंसा और हाल ही में संदेशखाली में महिलाओं से बलात्कार के मामलों से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है। हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार यह गलती नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में न सिर्फ राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, बल्कि ममता बनर्जी को सहानुभूति का फायदा भी मिल सकता है। यही वजह है कि संदेशाखाली की घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रदेश भाजपा की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने इस कोई फैसला नहीं लिया।

घोटालों और चुनावी हिंसा के कारण बदनामी का कलंक झेलने वाली ममता सरकार अब संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं से बलात्कार के मामले में सुर्खियों में है। संदेशखाली के सरगना शाहजहां शेख के आतंक की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भी उनके हमलों से सुरक्षित नहीं हैं। संदेशखाली में मनी लॉन्ड्रिंग में छापे के कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम को हमले का शिकार बनाया गया। जब अधिकारियों ने संदेशखाली में उसके घर में घुसने की कोशिश की तो 2,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने लाठी, डंडे और रॉड से हमला बोल दिया। इस घटना के बाद ही शेख के काले कारनामों का खुलासा हुआ। ममता सरकार ने इस मामले को दबाने-छिपाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस घटना की जानकारी लेने के लिए गए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को मौके पर नहीं जाने दिया गया। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी भी संदेशखाली कोर्ट की परमिशन से पहुंच सके।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में यौन उत्पीडन के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि शाहजहां शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने संदेशखाली मामले में पूरे मामले में राज्य की सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। अब सरकार को हाई कोर्ट में हलफनामा देना होगा। इस हलफनामे में सरकार को बताना होगा कि संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं के लिए अब तक क्या-क्या किया गया है? शाहजहां पर पहले भी गंभीर आरोप लगे थे। इसमें जबरन वसूली, हमला, बलात्कार और हत्या शामिल है। हालांकि उसे सजा नहीं हुई। 2020 में जब उस पर दो भाजपा नेताओं की हत्या का आरोप लगा तब भी वह फरार हो गया था। संदेशखाली प्रोटेस्ट के बाद उसके दो करीबियों शिबू हजारा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा चुनावी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में 2021 में राज्य चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये अंतरिम आदेश सीबीआई की उस याचिका पर दिया गया है, जिसमें सीबीआई ने राज्य में चुनावों के बाद हुई हिंसा के मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की

गुहार लगाई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और राज्य की एजेंसियां मूकदर्शक बनी हुई हैं।

पश्चिम बंगाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कथित तौर पर चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सात सदस्यीय समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर दिया था। हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था। आदेश मई 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, हिंसा के कारण अपने घरों से भागने वाले कई लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि सत्तारुढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के डर से वो अपने घर नही लौट पा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया जिसमें सरकार के 2 मंत्री संलिप्त हैं। राज्य के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इससे पहले ममता सरकार में कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, शारदा चिट फंड घोटाला, रोज वैली घोटाला हुआ है। ममता बनर्जी सरकार ने लगता है कि घोटालों का बंगाल माडल बना दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया। पैसे के बाद काम होने पर एक साल के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। 1.9 लाख करोड़ रुपये का ममता सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ममता सरकार ने 2018 से 2021 तक 2.4 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इसमें ग्रामीण विकास, शहरी विकास और शिक्षा मंत्रालय है। इन विभागों में ज्यादा भ्रष्टाचार है।

पश्चिम बंगाल में अपराधों के अलावा घोटालों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब एक दर्जन तृणमूल के नेता जेलों में बंद हैं। इनमें से ज्यादातर को जमानत तक नहीं मिल सकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लिया जिनके घर से करीब 20 करोड़ रुपए मिले थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर ई.डी. की टीम पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी के घर पहुंची थी। जब यह कथित घोटाला हुआ था, तब चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। मौजूदा परिदृश्य से यही लगता है कि ममता बनर्जी अपनी मर्जी के हिसाब से सरकार चलाना चाहती है। एनआईए, सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार या अपराधों के मामलों में देश के दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई की है, किन्तु जांच एजेंसियों को जिस तरह का हिंसात्मक विरोध का सामना पश्चिमी बंगाल में करना पड़ा है, वैसा देश के किसी भी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिला। घपले-घोटालों के एक भी मामलों से ममता सरकार मुक्त नहीं हो सकी। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में मजबूत राजनीतिक पकड़ बना रखी है।

यही वजह है कि पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में बनी हुई है। कांग्रेस, भाजपा और वाम दल पश्चिम बंगाल में जड़े जमाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन पूर्व के चुनावों तक ममता ने इन्हें टिकने नहीं दिया। सत्ता में लंबे समय से बने रहने का ममता बनर्जी ने शायद यह मतलब निकाल लिया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी मर्जी ही कानून है, यही वजह है कि ममता सरकार को विभिन्न मामलों में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार खानी पड़ी है। ममता बनर्जी को यह समझना है कि नेताओं की लोकप्रियता का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता है कि देश के कानून से खिलवाड़ किया जाए। यदि लोकप्रियता और सत्ता ही पैमाना होता तो देश में लालू यादव सहित दर्जनों ऐसे नेता हैं, जिन्होंने न सिर्फ सत्ता गंवाई बल्कि जेल का मुंह भी देखा है।

लद्दाख की हवा में बढ़ती राजनीतिक गर्मी को दूर करना होगा

शशिधर खान

पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लद्दाख में लगातार चल रहे जनआंदोलनों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख सिविल सोसाइटी संगठन नेताओं से बातचीत की। वार्ता को सार्थक कहा जाए या नहीं, इस पर कोई राय तभी बनाई जा सकती है, जब ठोस मुद्दे पर सहमति हो। लद्दाख के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर विचार करते को तैयार हो गई है, जबकि गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। विभिन्न मांगों को लेकर लद्दाखी सिविल सोसाइटी संगठनों की केंद्र से वार्ता दो वर्षों से चल रही है और गत हफ्ते की दिल्ली बैठक में तीसरे दौर की बातचीत हुई लेकिन हालिया 19 फरवरी और 24 फरवरी की बैठक में लद्दाखी नेताओं के तेवर निर्णायक दौर के मूडवाले थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाखी नेताओं को बुलाया भी उसी वक्त था, जब वहां की हवा में राजनीतिक गर्मी उफान पर आ गई। इस बार की बातचीत वैसे समय में हुई है, जब लद्दाखी नेता अपनी सबसे महत्वपूर्ण मांग को पत्थर की तरह ठोस बनाकर दिल्ली आए, इसलिए पहले की तरह तरल वायदों से शायद केंद्र सरकार का काम न चले। लद्दाखियों की प्रमुख मांगें हैं- लद्दाख यूटी (केंद्र शासित क्षेत्र) को पूर्ण राज्य और जनजातीय क्षेत्र का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग का गठन हो। इन मांगों में नंबर एक है, लद्दाख को राज्य का दर्जा। 19 फरवरी की बैठक में तय हुआ कि संयुक्त उपसमिति के साथ 24 फरवरी को इन मांगों पर चर्चा होगी। लेकिन किसी भी मांग पर सहमति बनने जैसी भनक नहीं मिली। श्रीनगर से छपनेवाले अखबार 'ग्रेटर कश्मीर' ने 25 फरवरी को लिखा कि 19 से 24 फरवरी तक सिर्फ इतना हुआ कि आंदोलनकारियों की मांगों पर चर्चा के लिए संयुक्त उप-समिति का गठन हुआ और उसकी पहली बैठक दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार लद्दाख को 'संवैधानिक सुरक्षा' प्रदान करने से एक भी कदम आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं है। 'संवैधानिक सुरक्षा' का तात्पर्य लद्दाख की परंपरागत संस्कृति, रीति-रिवाज, पर्यावरण और अपनी अलग पहाड़ी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा से जुड़े पहलुओं से है। 24 फरवरी की बैठक के बाद यह खबर आई कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है। चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटे होने के कारण लद्दाख का मामला संवेदनशील है। ऐसे में केंद्र को स्थानीय लोगों की भावना को समझना होगा। लद्दाखियों को विश्वास में लिए बगैर सीमा की सुरक्षा और इस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखना मुश्किल है।

छवियों से ही प्रतीक बनते हैं, जन-मन पर दिखेगा असर

बद्री नारायण

भारत में छवियों के अध्ययन का अभी तक कोई सुसंगत शास्त्र विकसित नहीं हो पाया है। इसके लिए शोध प्रविधि एवं इसके प्रभावों के अध्ययन, अंकन एवं मापन का काम सुसंगत ढंग से अभी होना बाकी है। छवियां मात्र छवियां नहीं होती हैं, वे धीरे-धीरे प्रतीकों में रूपांतरित हो हमारे मानस को गहरे प्रभावित करती हैं। इसी प्रक्रिया में वे जन-मन की गोलबंदी का स्वरूप रचती हैं। भारतीय राजनीति एवं चुनावों के अध्ययन में वृत्तांतों पर बातें तो होती हैं, पर छवियों पर व्यापक चर्चा नहीं होती। लोगों के बयानों के आधार पर सेफोलॉजी चुनावी परिणामों की व्याख्या तो करती रहती है, परंतु इस प्रक्रिया में छवियों के पड़ने वाले प्रभावों का न तो राजनीति-वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, न चुनाव विश्लेषक ज्यादा विचार करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि राजनीति में छवियां धीरे-धीरे बनती-बिगड़ती हमारी राजनीतिक कल्पनाशीलता को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव निर्माण की प्रक्रिया में वे किसी नेता, किसी राजनीतिक दल एवं किसी विचार के प्रति मतदाताओं को प्रभावित करती रहती हैं। कई बार छवियां विश्वास या अविश्वास का सृजन कर हमें चुनावी बूथों तक ले जाती हैं। वे हममें मोह रचती हैं एवं अनेक बार मोहभंग भी सृजित करती हैं।

मैं पिछले कई वर्षों से राजनीतिक नेताओं की छवियों का राजनीतिक एवं चुनावी गोलबंदी पर पड़ने वाले परिणामों के अध्ययन, चर्चा एवं विमर्श में शामिल रहा हूं। मैं राजनीतिक नेताओं की छवियों के बनने, बिगड़ने, उनमें आने वाले ठहराव एवं गतिकी को समझने की कोशिश करता रहता हूं। पिछले दिनों हमने उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों, जिलों एवं कस्बों के 20 से 30 वर्ष के युवाओं के साथ संवाद किया। ये युवा समाज की विभिन्न जातियों एवं वर्गों से थे। इनमें छात्र, छात्राएं, युवक एवं युवतियां, दोनों ही कोटि से जुड़े लोग थे। इनके साथ हुए संवादों से जो कुछ निहितार्थ निकले, वे बहुत रोचक एवं समकालीन राजनीति को समझने में सहायक हो सकते हैं। इन संवादों से यह समझ में आया कि नेताओं की छवियां मंथर गति से बढ़ती या घटती हैं। इनमें अचानक उछाल या गिरावट उनके

द्वारा किए गए बड़े कार्यों या घटनाओं से आती है। मैंने इन संवादों के केंद्र में मूलत: दो छवियों-भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रखा था।

प्रधानमंत्री मोदी की छवियों के वृत्तांतों में उन्हें प्राय: ईमानदार, लोभ-लालच एवं परिवारवाद से मुक्त एवं विकास के लिए समर्पित नेता बताने की प्रवृत्ति दिखी। कई युवा उन्हें देश एवं धर्म के प्रति समर्पित नेता मान रहे थे। यह जानना सबसे रोचक था कि उनमें से कई युवा उन्हें 'युग पुरुष% के रूप में भी देखने लगे हैं। उनका कहना था कि वे एक ऐसे नेता हैं, जो एक पूरे युग को रचने एवं प्रभावित करने वाला काम कर रहे हैं। इन युवाओं के मन में उनकी छवियों के जो वृत्तांत मुझे सुनने को मिले, उनसे दो बातें साफ लगीं। एक तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन छवियों में रामजन्मभूमि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद बड़ा उछाल आया है। उन्हें लोग युग पुरुष के रूप में देखने एवं कहने लगे हैं। उनकी युग पुरुष की छवि सामान्य युवाओं के मन में रामजन्मभूमि प्राण- प्रतिष्ठा समारोह के बाद की उत्पत्ति इसलिए मानी जानी चाहिए कि उसके पहले ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। दूसरा, उनकी छवि आज 'राजनीति से परे' (बियोंड पॉलिटिक्स) अपने में सामाजिक, धार्मिक एवं परिवारपन से जुड़ी छवियां शामिल किए हुए है। किसी भी राजनेता की जनछवियों में सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों ही प्रकार की धारणाएं होती हैं। लेकिन जनता के बयानों में छवियों के संदर्भ में प्राय: सकारात्मक वृत्तांत ज्यादा मिलते हैं। दूसरे, कई बार लोगों में उनके बारे में उदासीनता मिलती है। तीसरे स्तर पर आता है, छवियों की नकारात्मकता का बयान, जिसकी मात्रा या प्रतिशत प्राय: कम ही होता है।

राष्ट्रीय नेताओं में अन्य छवि जनता के मन में जिस नेता की बनती-बिगड़ती रहती है-वह हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने अनेक प्रतिरोधी राजनीतिक प्रयासों से अपनी छवि विकसित करते रहते हैं। उनकी छवियां अभी विकसित होने के क्रम में हैं। वे छवियां अभी प्रतीक में नहीं बदल पाई हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की छवियों के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनेक छवियां एक में सम्मिलित होकर प्रतीक में बदल कर अपना प्रभाव सृजित करती हैं। राहुल गांधी की कई छवियां या तो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं या जो विकसित हैं, उनका अभी संघनित सम्मिलन नहीं हो पाया है।

उनकी विद्यमान छवियों एवं युवाओं के एक वर्ग में-उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। कई युवा उनके 'एंग्री यंग मैन% की छवि से सहमत नहीं दिखे। उन्हें अपेक्षा है कि उनकी छवि राजीव गांधी जैसी सौम्यता वाली हो। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त बिल फाड़ने की घटना का जिक्र करते कई युवा मिले। उनकी छवि निर्माण के सलाहकार शायद यह सोचते हों कि भारतीय युवाओं को गुस्सा पसंद होता है। वे ऐसा सोचकर यह समझने में गलती करते हैं कि भारतीय मानस की आकांक्षा समाहार की होती है, टकराव की नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की राजनीति के प्रतीकात्मक नेतृत्व के रूप में राहुल गांधी की छवियों का विकास एवं विस्तार तो हुआ है, किंतु उन बहुल छवियों को एकीकृत हो एक राजनीतिक प्रतीक में बदलना अभी शेष है। जब तक छवियां प्रतीक में नहीं बदलतीं, वे दीर्घकालिक प्रभाव नहीं छोड़तीं। उनका प्रभाव क्षणिक होता है। आज राजनीतिक नेताओं की छवियों में परिवर्तन की गति तेज है। इसका प्रमुख कारण है-साइबर स्पेस, मीडिया-वैकल्पिक मीडिया, सोशल साइट्स का विकास एवं विस्तार। भारतीय युवा मानस चूंकि इस संचार नेटवर्क का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अत: उसके मानस में छवियों के परिवर्तन की गति ज्यादा तीव्र होती है। राजनीतिक नेताओं की बनती-बिगड़ती छवियां हर बार की तरह इस बार भी भारतीय चुनावों को प्रभावित करेंगी। देखना है, इस बार इनका प्रभाव कैसा होता है एवं किस प्रकार वे चुनाव परिणामों में परिवर्तन ला पाती हैं।

लोकतंत्र पर सवाल हैं निष्क्रिय सांसद

राज कुमार सिंह

नेता अक्सर बोलने के लिए जाने जाते हैं। कुछ तो बड़बोलेपन के लिए भी चर्चित रहते हैं। ऐसे में आपको हैरत होगी कि 17वीं लोकसभा में नौ सांसद ऐसे रहे, जिनका मौन पांच साल के कार्यकाल में भी नहीं टूट पाया। इनमें फिल्मी परदे पर दहाड़नेवाले वे हीरो भी शामिल हैं, जिनके डायलॉग सालों बाद भी दोहराये जाते हैं। लोकसभा और उसके सदस्यों के कामकाज के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि नौ सांसदों ने सदन में मौन तोड़े बिना ही अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। जाहिर है, उनके इस आचरण से उन्हें चुननेवाले लाखों मतदाता खुद को छला हुआ महसूस कर रहे होंगे, जिनकी उम्मीद थी कि उनके सांसद न सिर्फ क्षेत्र से जुड़े सवाल उठायेंगे, बल्कि देश और समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण संसदीय चर्चाओं में भी भाग लेंगे। ध्यान रहे कि सांसदों को कार्यकाल के दौरान भारी- भरकम वेतन-भत्तों के साथ तमाम सुविधाएं देने पर ईमानदार करदाताओं की मेहनत की कमाई में से ही मोटी रकम खर्च होती है। यदि वे पांच साल तक मौन और निष्क्रिय रहे, तब तो सब कुछ व्यर्थ ही गया। ये 'मौनी' सांसद किसी दल विशेष के नहीं हैं, पर यह आंकड़ा चौंकानेवाला है कि इनमें सबसे ज्यादा छह भाजपा के हैं, जिसके नेता भाषण कला में माहिर माने जाते हैं।

दूसरे पायदान पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसके दो सांसदों ने अपने कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछा। नौवें सांसद बसपा के अतुल कुमार सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश के घोसी से चुने गये, पर एक मामले में सजा काटते हुए उनका ज्यादातर समय जेल में ही गुजरा। पांच साल में एक भी सवाल न पूछने वाले भाजपा सांसदों में सबसे दिलचस्प मामला सनी देओल का है। वे पंजाब के गुरदासपुर से सांसद हैं, जहां से कभी एक और फिल्मी हीरो विनोद खन्ना सांसद हुआ करते थे। विनोद खन्ना केंद्र में मंत्री भी रहे। सनी देओल के पिता फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र भी 2004 से 2009 तक 16वीं लोकसभा

में राजस्थान के बीकानेर से भाजपा सांसद रह चुके हैं। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी अभी भी उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद हैं। गुरदासपुर में भी सनी देओल के गुमशुदा होने के पोस्टर लगते रहे यानी वे न तो संसद में सक्रिय रहे और न ही अपने मतदाताओं के बीच। अपने दौर के सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार धर्मेंद्र जब बीकानेर से सांसद थे, तब निर्वाचन क्षेत्र से उनके गायब रहने की चर्चाएं भी आम रहीं।

सनी देओल की फिल्म 'दामिनी' का एक अदालती दृश्य और उसमें यह डायलॉग बड़ा चर्चित हुआ था कि 'इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो बस तारीख पर तारीख'। पर गुरदासपुर के मतदाताओं की बेबसी देखिए, उन्हें तो वह तारीख भी नसीब नहीं हुई, जब वह अपने सांसद को लोकसभा में बोलते हुए देख-सुन पाते। पूरा कार्यकाल मौन में गुजार देनेवाले भाजपा के पांच अन्य सांसद रहे- प्रधान बरुआ, बीएन बाचे गौड़ा, अनंत कुमार हेगड़े, रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी और श्रीनिवास प्रसाद। बीजापुर के सांसद जिगाजिनागी के बारे में बताया जाता है कि वे खराब सेहत के चलते ज्यादातर समय सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाये। किसी अस्वस्थ व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता मानवीयता का तकाजा है, पर क्या ऐसी निष्क्रियता के बावजूद उनका सांसद बने रहना मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी-जवाबदेही का प्रमाण है? ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के जो दो सांसद पूरे कार्यकाल मौन रहे, उनमें एक पुराने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते रहे। एक डायलॉग तो उनकी जैसे पहचान ही बन गया- 'खामोश!' विडंबना देखिए कि भाजपा से राजनीति शुरू कर कांग्रेस के रास्ते तृणमूल कांग्रेस में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में अपने कार्यकाल के दौरान खामोश ही रहे।

नौवें 'मौनी' सांसद रहे दिव्येंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल के तामलुक से चुने गये। वैसे यह जानना भी दिलचस्प होगा कि 17वीं लोकसभा में भाजपा के दो सांसद भी ऐसे रहे, जो एक दिन भी सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित नहीं रहे। ये हैं- भगीरथ चौधरी और मोहन मांडवी। लोकसभा के कुल 543 सांसदों में से 141 सांसदों की सदन में उपस्थिति 90 प्रतिशत रही, पर 29 सांसद ऐसे भी रहे, जिनकी उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम रही। इनमें भाजपा और तृणमूल के आठ-आठ सांसद हैं। इनमें कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी हैं, जिनकी सेहत अच्छी नहीं चल रही। ऐसे अन्य सांसदों में चर्चित नाम ज्यादा हैं- मसलन, हेमा मालिनी, सनी देओल, किरण खेर और गायक हंसराज हंस। सनी देओल तो मात्र 17 प्रतिशत उपस्थिति के साथ लोकसभा में मानो 'गेस्ट एपीयरेंस' देते नजर आये। वैसे सनी देओल और किरण खेर मनोरंजन के क्षेत्र में खूब सक्रिय नजर आये। जाहिर है, राजनीतिक दल अपने निष्ठावान नेताओं को नजरअंदाज कर ऐसे सेलिब्रिटी को उनकी लोकप्रियता भुनाने के लिए ही टिकट देते हैं। ये सेलिब्रिटी भी अपनी लोकप्रियता भुना कर सत्ता के गलियारों में प्रवेश को लालायित रहते हैं, पर इससे राजनीति और लोकतंत्र को क्या हासिल होता है, इस पर मतदाताओं को अवश्य चिंतन-मनन करना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र को इस तरह मखौल बनाना और बनते देखना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले लोग हमारी सेना के आधुनिकीकरण के दुश्मन हैं

नीरज कुमार दुबे

देश इस समय विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है लेकिन बड़े सुनियोजित तरीके से जनता को इस लक्ष्य से भटकाने की और भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। किसानों को बहका कर आंदोलन खड़ा कराने के बाद अब सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ पर सवाल उठाकर नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी देशभर में घूम-घूमकर समाज में जातिवाद की भावना को उभारने का प्रयास पहले से कर ही रहे हैं। हो सकता है देशवासियों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतार कर और देश के संसाधनों को नुकसान पहुँचवा कर विपक्ष के नेताओं के हित सध जायें लेकिन इससे देश वो सब कुछ खो देगा जो पिछले 10 सालों में कड़ी मेहनत से अर्जित किया गया है। सत्ता की लालसा या महत्वाकांक्षा होना जायज है लेकिन देश के हितों की बलि देकर कुर्सी तक पहुँचने की योजना देश के लिए घातक है। हम आपको याद दिला दें कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ जब पेश की गई थी तब भी विपक्ष ने इसके बारे में भ्रम और अफवाहें फैला कर देश को अशांति की आग में झोंक दिया था। लगता है वैसा ही कुछ एक बार फिर करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि अग्निपथ योजना के बारे में सेना और सरकार युवाओं के भ्रम और इस योजना की विसंगतियां दूर कर इसे दुनिया की सबसे पारदर्शी और उत्कृष्ट भर्ती नीति बना चुकी है। इस नीति से युवा कितने खुश हैं इसका अंदाजा तभी लग गया था जब तीनों सेनाओं में आवेदनों के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गये थे। जो लोग कह रहे हैं कि चार साल की सेवा के बाद नौजवान को फिर से नौकरी की खोज करनी होगी, दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार और निजी क्षेत्र ने अग्निवीरों के लिए क्या-क्या प्रबंध किये हैं। देखा जाये तो अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले हमारी सेना के आधुनिकीकरण के भी दुश्मन हैं। इसे उदाहरण के जरिये समझना है तो देखिये कि आज के दौर में बड़े-बड़े महारथियों को युद्ध क्षेत्र में एक एक दिन गुजारना भारी पड़ रहा है। सैन्य रूप से ताकतवर देशों में शुमार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया मगर दो साल बाद भी यूक्रेन को पूरी तरह हरा नहीं पाया है। सर्वाधिक आधुनिक हथियारों से युक्त देश माने जाने वाले इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ अभियान छेड़ा, मगर पांच महीने होने को आये लेकिन इजराइल को जीत नहीं मिली है। लाल सागर में देख लीजिये कैसे हूती विद्रोहियों ने अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की नाक में दम कर रखा है। यह सब उदाहरण इस बात की आवश्यकता पर जोर देते हैं कि सैन्य मामलों में हर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए और सेना के जवान इस आधुनिक युग के युद्धों से लड़ने के अलावा भविष्य के युद्धों से लड़ने के योग्य और विशेष रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए। बहरहाल, यहां इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस ने सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू की थी और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। 2019 में पुलवामा हमले का जब भारतीय वायुसेना ने बदला लिया था तो विपक्षी दलों ने इसके सबूत मांगे थे। यही नहीं, राफेल लड़ाकू विमान सौदे में घोटाले का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की गयी थीं और चुनावों के समय भरसक प्रयास किया गया था कि देश में इस विमान सौदे के खिलाफ माहौल बने ताकि सरकार इसे रद्द करे। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं तो कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। विपक्ष को समझना चाहिए कि सेना से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा ऐसा मुद्दा है जिससे कतई समझौता नहीं किया जा सकता।

स्प्रिंग सीजन में बढ़ जाती है भारत की इन जगहों की खूबसूरती

भारत में फरवरी से वसंत ऋतु का अनुभव होने लगता है, यह मार्च तक रहता है। इस दौरान मौसम हल्का गर्म और सुखद होता है। इस मौसम के दौरान सर्द सर्दियों से राहत मिल जाती है। ऐसे में घूमने-फिरने के लिए ये मौसम परफेक्ट है। यहां उन जगहों के बारे में बता रहे हैं जो इस सीजन के दौरान और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। देखिए, स्प्रिंग सीजन में घूमने के लिए बेस्ट प्लेसिस-

दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल

हरियाली से ढका दार्जिलिंग एक फेमस हिल स्टेशन है। इस जगह को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहां घूमने लायक कई जगह हैं। जैसे टाइगर हिल, बतासिया लूप, नाइटिंगेल पार्क, दार्जिलिंग रॉक गार्डन, दार्जिलिंग पीस पैगोडा और कुछ चाय के बागान शामिल हैं। बसंत ऋतु के दौरान इन जगहों की खूबसूरती दो गुना बढ़ जाती है।

वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड

उत्तराखंड में मौजूद वैली ऑफ फ्लावर स्प्रिंग सीजन में घूमने के लिए बेस्ट है। कहा जाता है कि यहां फूलों की यहां पर 300 से ज्यादा अलग-अलग तरह के फूल हैं। इसमें कुछ ऐसे फूल है जो देश के किसी दूसरी जगह पर नहीं मिलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर के आसपास आप ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

बीर, हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा जिले में बीर नाम का एक छोटा सा गांव है। जहां से आप बेहद खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। पर्यटन के लिए ये जगह फेमस है। यहां पर चोकलिंग मठ, गुनेहर झरना, बैजनाथ मंदिर, पालपुंग शेरबलिंग मठ, डियर पार्क इंस्टीट्यूट और ताशी जोंग मठ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैंग ग्लाइडिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी करने के लिए यहां पर अलग-अलग देशों से लोग पहुंचते हैं।

जीरो वैली, अरुणाचल

वसंत ऋतु में अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में जा सकते हैं। यहां मेघना गुफा मंदिर, जीरो प्लूटो, दिलोपोलीयांग मनिपोलियांग, तारिन फिश फार्म, टैली वैली और किले पाखो की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। आप पेंज नदी बेसिन के पास जीरो वैली में कैंपिंग के लिए जा सकते हैं। यहां खिले हुए फूलों और रंग-बिरंगे पक्षियों का आनंद ले सकते हैं।

मार्च के महीने में दोस्तों के साथ भारत की इन खास जगहों का टूर करें, एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाएं

मार्च का महीने में गर्मी कम होती है ऐसे में लोग घूमने का प्लान बनाते है। इस दौरान कई बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते है। वह अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं न कहीं घूमने जाते है। मार्च का महीना में न ठंड होती है और न ज्यादा गर्मी होती है। यह मौसम घूमने का सबसे बेस्ट होता है। पर्टनर के साथ घूमने के लिए यह समय काफी अच्छा है। वहीं, इस समय पूर्व से लेकर दक्षिण तक मौसम काफी कूल होता है। मार्च में दोस्तों के साथ घूमने का अलग ही मजा होता है। जब भी आप कही घूमने का प्लान बनाते हैं, तो ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां मस्ती कर सके है, तो देर किस बात कि इस आर्टिकल में हम बताएंगे भारत की शानदार जगहें जिन्हें आप अपने घूमने का डेस्टिनेशन बना सकते हैं।

ऋषिकेश

योग नगरी के नाम से फेमस ऋषिकेश उत्तराखंड का एक शानदार और खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां पर जाना हर किसी का ड्रीम होता है। पहाड़ों का नजारा, झील, झरने, गंगा नदी और घने जंगल ऋषिकेश के आकर्षक केंद्र माना जाता है। यहां पर मस्ती और धमाल के लिए सबसे बढ़िया जगह है। इसी के साथ आप रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग का बेहतरीन मजा उठा सकते हैं। ऋषिकेश में कैम्पिंग का लुत्फ उठा सकते हैं।

गोवा

गोवा भारत की ऐसी जगह जहां लोग बीच का मजा और वाटर एक्टिविटीज करने के लिए प्लान बनाते हैं। गोवा में सुनहरे समुद्र तटों के लिए पूरे विश्व भर में फेमस है। इसके अलावा शानदार पार्टियां और नाइटलाइफ के बीच आप दोस्तो के साथ यादगार वैकेशन मना सकते हैं। मस्ती और धमाल के लिए गोवा में दूधसागर जलप्रपात, अंजुना बीच, वागाटोर बीच और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जैसलमेर

जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख शहर में से एक है, यहां एक लोकप्रिय पर्यटन भी स्थल है। थार रेगिस्तान की वजह से इसे गोल्डन शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा शहर है, जहां आप अपने दोस्तों के साथ डेजर्ट सफारी का शानदार मजा लें सकते हैं। यहां पर आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। जैसलमेर में आप जैसलमेर फोर्ट, गडीसर झील और पटवों की हवेली जैसी शानदार जगहों पर घूम सकते हैं। इसके साथ ही आप राजस्थानी कल्चर और नृत्य देख सकते हैं इसके साथ ही राजस्थानी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं।

हम्पी

अगर आप दक्षिण भारत का टूर करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ मार्च के महीने में हम्पी घूमने का प्लान बना सकते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल आप मस्ती करने के लिए हम्पी जा सकते हैं। हम्पी शहर की नाइटलाइफ आपकी यात्रा में चार चांद लगा देगा। यहां पर स्थित पहाडियों और घाटियों का विशेष आकर्षक केंद्र है। हम्पी में विरुपाक्ष मंदिर, रानी का स्नानागार, मतंग हिल और लोटस महल जैसी बेहतरीन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कोलकाता के नजदीक हिल स्टेशनों की खूबसूरती देख रह जाएंगे दंग

कोलकाता एक ऐसा शहर है, जहां पर अक्सर लोग घूमने-टहलने व समय बिताने के लिए आते हैं। कोलकाता जैसे जीवंत शहर में आप कई बेहतरीन जगहों पर घूम सकते हैं। यहां पर आप बोटेनिकल गार्डन से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल तक कई जगहों पर पार्टनर संग अच्छा समय बिता सकते हैं। वहीं अगर आप यहां पर हिल स्टेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि हिल स्टेशन भीड़-भाड़ से दूर आपको सुकून का एहसास कराते हैं।

अगर आप भी कोलकाता घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहां पर मौजूद कुछ हिल स्टेशनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यहां आने के बाद एक अलग तरह के सुकून का एहसास होगा।

कोलकाता एक ऐसा शहर है, जहां पर अक्सर लोग घूमने-टहलने व समय बिताने के लिए आते हैं। कोलकाता जैसे जीवंत शहर में आप कई बेहतरीन जगहों पर घूम सकते हैं। यहां पर आप बोटेनिकल गार्डन से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल तक कई जगहों पर पार्टनर संग अच्छा समय बिता सकते हैं। वहीं अगर आप यहां पर हिल स्टेशन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि हिल स्टेशन भीड़-भाड़ से दूर आपको सुकून का एहसास कराते हैं। कोलकाला के करीब इन हिल स्टेशन्स पर आप परिवार के साथ आएं या अकेले, यकीनन आपको यहां पर काफी अलग एहसास होगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कोतकाता में स्थित कुछ हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं।

अजोध्या हिल्स

समुद्र तल से 855 मीटर की ऊंचाई पर अजोध्या हिल्स स्थित है। यह हिल स्टेशन कोलकाता के सबसे करीब है। साथ ही प्रभु राम के वनवास पर एक पड़ाव स्थल के रूप में भी यह जगह काफी ज्यादा फेमस है। यहां पर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक है। यहां पर आप टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, डिमना झील और दलमा वाइल्डलाइफ सैन्चुरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर रॉक क्लाइम्बिंग व ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

सिमुलतला

वैसे तो सिमुलतला हिल स्टेशन इतना ज्यादा डेवलप टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन यहां पर आप काफी अच्छा समय बिता सकते हैं। सिमुलतला बिहार का एक छोटा सा गांव है। यह उन हिल स्टेशन की लिस्ट में आता है, जो व्यस्त शहरी लाइफस्टाइल से दूर शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं। यहां का आदर्श जलवायु और नेचुरल खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। यहां पर आप घाटियां और झरने भी देख सकते हैं। वहीं खाने के शौकीन लोग अनोखे व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आपको यहां पर सबसे फेमस मिठाई छन्ना-मुरकी का स्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए।

नेतरहाट

कोलकाता से नेतरहाट की दूरी करीब 575 किमी दूर है। यह छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी फेमस है। झारखंड के लहार जिले में स्थित नेतरहाट एक खूबसूरत जगह है। यह जगह सनसेट और सनराइज के नजारों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आप भी कोलकाता की ऑफबीट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो नेतरहाट परफेक्ट जगह है। यहां पर आप कोयल व्यू पॉइंट, सदनी फॉल्स मैगनोलिया पॉइंट और लोध फॉल्स आदि जगहें घूमना न भूलें। यहां पर आप रॉक क्लाइम्बिंग को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं।

कुर्सियांग

पश्चिम बंगाल का कुर्सियांग हिल स्टेशन बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। यहां पर आप शानदार माउंटेन स्लोप, चर्च और चाय के बागानों को देख सकते हैं। भारत के सबसे हिल स्टेशन में इसकी गिनती होती है। यहां पर आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं।

भारत के इन बीचेज पर तैरने से पहले जरूर बरतें ये सावधानियां

भारत देश में ऐसे कई बीचेस हैं, जहां पर स्विमिंग आदि करना बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे बीचेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर घूमना व स्विमिंग करना ज्यादा सेफ नहीं है।

जब भी वेकेशन टाइम होता है, तो लोग कहीं न कहीं घूमने का प्लान जरूर बना लेते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को पहाड़ों पर तो कुछ लोगों को बीचेस पर वेकेशन मनाना पसंद होता है। वैसे बीचेस पर मस्ती करना लगभग हर किसी को पसंद होता है। आपको बता दें कि भारत में ऐसे कई डेस्टिनेशन हैं, जहां पर आप बीच पर घूमते हुए ढेर सारी मस्ती कर सकते हैं। हांलाकि आप हर बीच पर उतनी ही मस्ती कर सकें, यह जरूरी नहीं है।

दरअसल, भारत देश में ऐसे कई बीचेस हैं, जहां पर स्विमिंग आदि करना बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे बीचेस के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर घूमना व स्विमिंग करना ज्यादा सेफ नहीं है। तो आइए जानते हैं भारत में मौजूद इन बीचेस के बारे में...

अरम्बोल बीच, गोवा

वहीं गोवा का अरम्बोल बीच काफी ज्यादा फेमस है। यहां पर अक्सर लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आते हैं। अरम्बोल बीच जितना ज्यादा खूबसूरत है, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। यह बीच एक चट्टानी इलाके में है। हांलाकि अरब सागर की तेज लहरें स्विमिंग को मुश्किल बनाती हैं। इसके अलावा पानी के नीचे छिपी बड़ी चट्टानों की वजह से आपको स्विमिंग के दौरान अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

मरीना बीच, चेन्नई

चेन्नई का प्लान बनाने वाले लोग मरीना बीच घूमने जरूर जाते हैं। बता दें कि मरीना बीच को दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक माना जाता है। इसलिए अगर आप यहां पर स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस बीच की गहराई में जाने को लेकर अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए।

यारदा बीच, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास याराडा बीच स्थित है। यह बीच हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस बीच की खूबसूरती को देखते हुए लोग यहां पर वक्त बिताना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहां की तेज लहरें इसको देश की सबसे खतरनाक बीचेस बनाती हैं। ऐसे में अगर आप भी यहां पर आते हैं, तो आपको यहां काफी सोच-समझकर स्विमिंग करनी चाहिए।

कोवलम बीच, केरल

कोवलम बीच केरल में बेहद पॉपुलर बीच है। अक्सर लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ यहां आना पसंद करते हैं। लेकिन यहां आने के दौरान थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। क्योंकि तेज लहरें होने की वजह से यहां पर डूबने की दुर्घटनाएं देखी गई हैं। इसलिए अगर आप इस बीच पर जाते हैं, तो वॉर्निंग साइंस को अनदेखा न करें। इसके साथ ही लाइफगार्ड इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करें।

डुमस बीच, गुजरात

गुजरात के डुमस बीच पर अक्सर लोग जाने से कतराते हैं। यह देश के सबसे रहस्यमयी समुद्र तटों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हॉन्टेड बीच है। इसलिए जब लोकल लोग इस बीच पर आते हैं, तो पानी में बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं। लोगों के मन में इस बीच को लेकर बनी धारणा इसको अनोखा और खतरनाक बनाती है।

● अनन्या मिश्रा

द्वारकाधीश से जुड़े हैं कई फैक्ट्स

पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका भारत का एक प्राचीन शहर है। यहां गोमती नदी के तट पर मौजूद द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन और इसके आसपास घूमने के लिए आते है। इस मंदिर से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग और पौराणिक फैक्ट्स के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़े फैक्ट्स-

सालों पुरानी है मंदिर की वास्तुकला

द्वारका शहर का इतिहास महाभारत में द्वारका साम्राज्य के समय का है। द्वारकाधीश मंदिर पांच मंजिला है, जिसे चूना पत्थर और रेत से बनाया गया है। कहते हैं कि 2200 साल पुरानी वास्तुकला उनके पोते वज्रनाभ द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इसे भगवान कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त भूमि पर बनाया था। मंदिर के अंदर दूसरे मंदिर हैं जो सुभद्रा, बलराम और रेवती, वासुदेव, रुक्मिणी और कई अन्य को समर्पित हैं। इस मंदिर में अंदर जाने से पहले भक्तों को गोमती नदी में डुबकी लगानी होती है।

कई बार बदला जाता है मंदिर का ध्वज

दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर की चोटी पर भी एक ध्वज लहराता है, जिसे भक्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं।

दुबई जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 साल तक होगा वीजा वैलिड

दुबई जाने वाले भारतीय हर साल लाखों जाते हैं। ऐसे में सऊदी अरब ने भारतीय पर्यटको के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है, अब दुबई जाने के लिए 5 साल तक वैलिड रहेगा वीजा। सऊदी अरब सरकार ने भारतीय लोगों को बेहतरीन ऑफर दिया है, अगर आप भी दुबई जाने का प्लान सोच रहे तो अब 5 साल तक वीजा वैलिड है।

विदेश जाने की रुचि रखने वाले सभी भारतीयों के लिए बड़ी खबर है। घूमने, करोबार और कामकाज के लिए कई बार हर भारतीय दुबई जरुर जाता है। ऐसे में सऊदी अरब अमीरात ने भारतीय पर्यटको बड़ी सौगात दी है, अब हर भारतीय दुबई जरुर घूमने जाता है। यह हम सभी जानते हैं कि दुबई जाने के लिए पासपोर्ट के साथ-साथ वीजा होना काफी जरुरी है। ऐसे में दुबई सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा लेकर आया है।

आखिर क्या है 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा

बता दें कि, 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा के बारे मे कहा जा रहा है, वीजा रिक्वेस्ट करने के 2 से 5 दिनों के अंदर वीजा जारी हो जाएगा। इसी के साथ वीजा पाने वाला व्यक्ति दुबई में 90 दिन रुक सकता हैं।

अगर आपको जरुरत पड़ती है तो फिर 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मल्टीपल एंट्री वीजा लेने के बाद पर्यटक इस वीजा में एक साल में 180 दिन से अधिक नहीं रुक सकता है।

5 साल तक होगा वीजा वैलिड

इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पर्यटकों के लिओ टूरिस्ट वीजा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। इस ऑफर के जरिए सऊदी अरब में पांच साल आराम से घूम सकते हैं।

कई बार जा सकते हैं

5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा के बारे में बताया कि पर्यटक अब इस वीजा के जरिए से सऊदी में कई बार एंट्री कर सकता हैं। आपको बता दें, यह ऑफर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी है।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा के ऑफर से पर्यटन में काफी इजाफा होगा। भारत के अलावा अन्य देश के लोग यहां लाखों संख्या में आते है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में दुबई घूमने वाले लोग करीब 2.46 मिलियन थे। वहीं साल 2022 में अकड़ा करीब 1.84 मिलियन था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राज्यसभा चुनाव में हार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव परेशान!

लखनऊ। राज्यसभा चुनावों में मात के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिहाज से आजमगढ़ की किलेबंदी में जुट गए हैं। इसके लिए आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बुधवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हो गया। आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से दो बार बसपा के टिकट पर विधायक रहे चुके गुड्डू जमाली के दो साल पहले आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा के टिकट पर गुड्डू जमाली के चुनाव मैदान में उतरने से सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। अब गुड्डू जमाली को सपा की सदस्यता दिलाकर अखिलेश यादव आजमगढ़ के अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गए हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आजमगढ़ के मुबारकपुर के रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वर्ष 2012 और वर्ष 2017 से वह बसपा के सिंबल पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।

कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का हिमाचल कैबिनेट से इस्तीफा

शिमला। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को एक आश्चर्यजनक कदम में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे की घोषणा की। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे ने भी कहा कि अब सब कुछ कांग्रेस आलाकमान के पाले में है। 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। बाकी तीन सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ खुलकर सामने आते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मैंने सरकार के कामकाज के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज स्पष्ट रूप से कहना मेरी जिम्मेदारी है...मैंने हमेशा कहा है कि पद और कैबिनेट में जगह मिलती है। मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश की जनता से रिश्ता...लेकिन पिछले एक साल में सरकार में जिस तरह की व्यवस्था रही, जिस तरह से विधायकों की अनदेखी की गई और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई - यह उसी दल से आप सबको सतर्क रहने और अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है।

मोदी ने कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है, जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तमिलनाडु के विकास की आड़ में आपको लूटा है। उन्होंने युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को कुचल दिया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया कुछ दिन पहले इसे लेकर संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था। डीएमके के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गये। यह व्यवहार दर्शाता है कि डीएमके नेता आपकी आस्था का कितना तिरस्कार करते हैं। डीएमके और कांग्रेस देश को बांटने पर तुले हुए हैं। जबकि भाजपा हर व्यक्ति को परिवार का सदस्य मानती है।

राज्यसभा में भाजपा को बढ़त बहुमत से 4 कदम दूर एनडीए

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 240 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े 121 से केवल चार पीछे है। मंगलवार को, भाजपा ने 10 राज्यसभा सीटें जीतीं - और पहले 20 निर्विरोध। अप्रैल में छप्पन राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है जिसके लिए चुनाव हुए थे। इन 30 सीटों की जीत के साथ, सभी 56 सदस्यों के शपथ लेने के बाद, राज्यसभा में भाजपा की संख्या 97 और एनडीए की संख्या 117 हो जाएगी। भाजपा 97 सदस्यों के साथ राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, जिसमें पार्टी में शामिल हुए पांच नामांकित सांसद भी शामिल हैं, इसके बाद 29 सदस्यों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। पांच रिक्तियों को शामिल करने के बाद राज्यसभा की ताकत अब 240 हो जाएगी-चार जम्मू और कश्मीर से और एक मनोनीत सदस्य श्रेणी से। तीन राज्यों की 15 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, जिसमें भाजपा ने 10 सीटें जीतीं।

मायावती लोकसभा चुनाव में जा सकती हैं भाजपा के साथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि मायावती बहुजन समाज पार्टी पार्टी की टूट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बलिया से इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह द्वारा बीते मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने और बसपा सांसदों में मची भगदड़ को देखते हुए राजनीतिक हलकों में अटकलें लग रही हैं कि बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो सकती है। अब तक बसपा ने एनडीए और इंडिया दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखी थी। लेकिन अब बलिया की रसड़ा सीट से बसपा के विधायक उमा शंकर सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को भाजपा उम्मीदवार को अपना वोट दिया है।

शाहजहां को सीबीआई-ईडी भी कर सकती हैं गिरफ्तार: कोर्ट

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी और फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस के साथ-साथ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी गिरफ्तार कर सकते हैं। बंगाल के अटॉर्नी जनरल की अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया। कोर्ट ने पहले ही पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बता दें कि शाहजहां शेख संदेशखाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली डिविजनल बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी।

प्रधानमंत्री बोले- तमिलनाडु का विकास मोदी की गारंटी

देश को बांटने पर तुले डीएमके और कांग्रेस

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तिरुनेलवेली में उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं यहां उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्न हूं। तिरुनेलवेली के हलवे की तरह ही इस जिले के लोग भी बहुत मीठे हैं। पिछले 2 दिनों में मैं जिन भी स्थानों पर गया हूं, वहां मैंने देखा है कि तमिलनाडु का प्रत्येक वर्ग आत्मविश्वास के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि लोग देखते हैं कि कैसे भाजपा ने संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दिया है। तमिलनाडु के लोगों के इस अपार प्यार और समर्थन को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भाजपा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मोदी ने कहा कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, गरीब और मिडिल क्लास, तमिलनाडु का हर वर्ग, हर समाज आज पूरे विश्वास के साथ भाजपा के साथ आ रहा है। तमिलनाडु के लोग भाजपा को बड़ी आशाओं से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं कि कैसे भाजपा ने देश में संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है। तमिलनाडु का ये असीम प्रेम, ये विश्वास हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने तमिलनाडु के लोग भविष्य की जरूरतों को स्वीकार करते हैं। वे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और नई सोच के लिए जाने जाते हैं। यह तमिलनाडु को बीजेपी के और भी करीब लाता है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमें उन कुछ देशों में से एक होने पर गर्व है जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब हम नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि तमिलनाडु इस क्षेत्र में अवसरों से भरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है। आज दुनिया हमारे तमिल प्रवासियों को सम्मान की दृष्टि से देखती है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह बदलाव केंद्र में भाजपा की मजबूत और स्थिर सरकार के कारण आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अगर देश 100 कदम आगे बढ़ता है, तो तमिलनाडु भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए बीते 10 वर्षों में अगर हमने देश में अनेक नए एम्स खोले तो मदुरई में भी एम्स खोलने

जा रहे हैं। उन्होंने आज अगर देश में हर गरीब को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल रही है, तो उसमें 50 लाख से ज्यादा लाभार्थी हमारे तमिलनाडु के भाई-बहन हैं। और ये सेवा हम तब कर रहे हैं, जब राज्य में ऐसी सरकार है जो तमिलनाडु के हित के लिए भी हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है। इसलिए तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से, ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक

प्रधानमंत्री ने थूथुकुडी में 17,300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने थूथुकुडी में करीब 17,300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल शामिल है। वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद, थूथुकुडी के निकट कुलसेकरापट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास किया, जिसकी लागत लगभग 986 करोड़ रुपये है। बताया जा रहा है इसके बनकर तैयार होने पर यहां से प्रति वर्ष 24 प्रक्षेपण किए जा सकेंगे। इसरो के इस नए परिसर में 'मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर' (एमएलएस) तथा 35 केंद्र शामिल हैं। इससे अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं यूपीए सरकार पर सीधा-सीधा आरोप लगा रहा हूं। जो प्रोजेक्ट्स मैं आज लेकर आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में सरकार चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज मैं तमिलनाडु की धरती पर इस राज्य का भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को लॉन्च किया गया है। यह फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलेगी, यह एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइटहाउस को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। आज मुझे देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित 75 लाइटहाउस में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है...यह नया भारत है।

हिमाचल प्रदेश में जो जनादेश मिला है उसे पूरा करेंगे

कांग्रेस सरकार गिराना मोदी की गारंटी: जयराम रमेश

नईदिल्ली। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार खतरे में दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव में वोट के बाद पार्टी में बगावत देखने को मिली है। इसी कड़ी में कांग्रेस अब भाजपा पर हमलावर हो गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार गिराना ही मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला वहां हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है। उन्होंने सभी विधायकों से मिलकर उनकी शिकायतों और मांगों को सुनने को कहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई। लेकिन कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश हुई। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन लोटस से निपटने के लिए पार्टी को क्या कदम उठाने हैं- कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने इन वरिष्ठ सहयोगियों से कहा है कि वे सभी से मिलें और उनकी बातों को सुनें और उन्हें बताएं यथाशीघ्र रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि सभी की बात सुनने के बाद जल्द से जल्द पर्यवेक्षकों द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके आधार पर पार्टी अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बात कर आगे कदम जरूर उठाया जाएगा। हो सकता है कि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ें लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। संगठन सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च है।

उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता अपनी कांग्रेस सरकार को बचाना है क्योंकि दिसंबर 2022 में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने पीएम, जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर को खारिज कर दिया था। जनादेश कांग्रेस पार्टी के लिए था...इसलिए इस जनादेश का सम्मान किया जाना

चाहिए...मोदी सरकार की एक ही गारंटी है- सभी कांग्रेस सरकारों को गिरा दो। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

अपने इस्तीफे की खबर को सीएम सुक्खू ने किया खारिज

शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि न तो किसी ने मुझसे इस्तीफा मांगा और न ही मैंने अपना इस्तीफा किसी को दिया है। हम बहुमत साबित करेंगे। हम जीतेंगे, हिमाचल की जनता जीतेगी। उन्होंने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं और मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब बजट पेश किया जाएगा तो कांग्रेस जीतने वाली है। आज बजट पास होगा। बीजेपी मेरे इस्तीफे की अफवाह फैला रही है। कांग्रेस एकजुट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी मेरे इस्तीफे की अफवाह फैला रही है। वे विधायक दल में टूट कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर उनके साथ आ जाएं। कांग्रेस एकजुट है...बीजेपी को वोट देने वाले कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। इससे पहले कहा गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सुक्खू का इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा से पद छोड़ने की पेशकश की।

खेल
प्रमुख समाचार

धर्मशाला टेस्ट में होगी केएल राहुल की वापसी?

धर्मशाला। इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया और 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। अब टीम की नजर पांचवें टेस्ट पर है जो धर्मशाला में सात मार्च से खेला जाएगा। इस मैच में केएल राहुल की वापसी होगी या नहीं बड़ा सवाल है। दरअसल, हैदराबाद टेस्ट के बाद चोट की वजह से विकेटकीपर बल्लेबाज अगले तीन मैचों में टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि, फैंस को उम्मीद है कि वह अंतिम मुकाबले में वापसी कर सकते हैं।

इस बीच केएल राहुल को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केएल राहुल इस वक्त लंदन में हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में धर्मशाला मैच में उनकी उपलब्धता अब तक स्पष्ट नहीं है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद स्टार खिलाड़ी को दूसरे टेस्ट में आराम दिया गया था। वहीं, तीसरे टेस्ट से पहले खबर आई थी कि स्टार बल्लेबाज 90 प्रतिशत फिट हो चुके हैं। हालांकि, चौथे टेस्ट में भी वह टीम का हिस्सा नहीं बन सके। भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच में केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने विरोधी टीम के खिलाफ पहली पारी में 86 और दूसरी पारी में 22 रन बनाए। भारत के लिए 50 टेस्ट मुकाबलों में 2863 रन बना चुके राहुल की पांचवें टेस्ट में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। इस सीरीज के चौथे मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। उनके वर्कलोड को मैनेज करने के उद्देश्य से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुमराह को आराम देने का फैसला किया। उनकी जगह आकाश दीप को मौका मिला और उन्होंने डेब्यू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पांचवें टेस्ट में बुमराह की वापसी हो सकती है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भारी मुनाफावसूली के चलते 1% से ज्यादा गिरे सेंसेक्स, निफ्टी

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में 28 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 790.34 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 72,304.88 के स्तर तक नीचे चला गया तो वहीं एनएसई निफ्टी भी 247.20 अंक गिरकर 21,951.15 अंक पर पहुंच गया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और एलएंडटी में मुनाफावसूली की वजह से इक्विटी बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी बैंकों, ऑटो सेक्टर और ऑयल ऐंड गैस कंपनियों के शेयरों में करीब 2 फीसदी से लेकर 3.5 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते मार्केट पर निगेटिव असर देखने को मिला। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 1.8 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.9 फीसदी की गिरावट की वजह से भी बाजार पर निगेटिव असर पड़ा।

स्पाइसजेट ने सेलेस्टियल एविएशन के चुकाए 250 करोड़

नईदिल्ली। भारतीय एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने 28 फरवरी को जानकारी दी कि उसने विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी सेलेस्टियल एविएशन को 29.9 मिलियन डॉलर यानी करीब 250 करोड़ रुपये अदा कर दिया है और बातचीत के जरिये विवाद को सुलझा लिया है। AerCap की सब्सिडियरी कंपनी स्पाइसजेट ने सेलेस्टियल एविएशन के साथ समझौता कर मुकदमेबाजी से बचते हुए अपने 250 करोड़ रुपये के विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा लिया है। स्पाइसजेट ने इस मामले के सेटलमेंट की वजह से करीब 235 करोड़ रुपये बचा लिए हैं। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में एयरलाइन ने बताया कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने पिछले सप्ताह एनसीएलटी की एक बेंच को यह जानकारी दी थी कि सेटलमेंट की शर्तें पूरी हो गई हैं और साथ ही विवाद को खत्म करने का अनुरोध भी किया।

फूड सेक्टर में होगा 60000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में हुए बंपर निवेश और परियोजनाओं केधरातल पर उतरने के बाद रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। हाल ही में संपन्न ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत उत्तर प्रदेश में फूड प्रॉसेसिंग सेक्टर में 60000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा गया है, जिसके तहत सिर्फ बड़ी परियोजनाओं से ही प्रदेश में 3000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। औद्योगिक विकास विभाग का मानना हैं कि ये नौकरियां बिजनौर, मुजफ्फरनगर, संडीला, बरेली और बागपत जैसे जिलों में सृजित होने जा रही है। यही नहीं, तमाम अन्य बड़ी कंपनियां भी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में फूड प्रॉसेसिंग में निवेश कर रही हैं जो हजारों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। कोका-कोला के लिए भारत का सबसे बड़ा बॉटलर एसएलएमजी उत्तर प्रदेश में एक और शुगर सिरप, जूस मैन्युफैक्चरिंग, पल्प एक्सट्रैक्शन और बॉटलिंग यूनिट स्थापित कर रहा है।

रिलायंस कैपिटल को डीलिस्ट करने की तैयारी में हिंदुजा ग्रुप

नईदिल्ली। कारोबारी अनिल अंबानी की भारी कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल अब हिंदुजा ग्रुप की हो गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के 9,650 करोड़ रुपये के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। अब इसके नए मालिक यानी कि हिंदुजा समूह ने रिलायंस के शेयरों को समाप्त करके एक्सचेंजों से स्टॉक को हटाने की योजना बनाई है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, रिलायंस कैपिटल के इक्विटी शेयरधारक का परिसमापन मूल्य शून्य है और इसलिए, इक्विटी शेयरधारक कोई भुगतान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे और आरसीएल के किसी भी शेयरधारक को कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। बता दें, ट्रिब्यूनल ने डेट रिजॉल्यूशन प्रोसेस के तहत हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगी

डॉ. शंकर सुवन सिंह

भारत ऋषि परंपरा का देश रहा है। युग को चार भागों में विभाजित किया गया है- सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। ये सभी युग अपनी विशेष तकनीकी और प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार, पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगीरा ने बनाई थी। पुष्पक विमान की कार्य क्षमता और उसके निर्माण का श्रेय भगवान् विश्वकर्मा को जाता है।

आध्यात्मिक बल पर प्राप्त की गई शक्तियों का सबसे अच्छा उदाहरण पुष्पक विमान और हमारे वेद हैं। अपने देश में निर्मित वस्तु, विचार, अध्यात्म और प्रकृति आदि कारक स्वदेशी होने को परिलक्षित करते हैं। प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिक दर्शन के बल पर विकसित था और आज का भौतिक दर्शन के बल पर विकाशशील है। जब भारत में आध्यात्मिक दर्शन, भौतिक दर्शन के साथ कदम मिलाकर चलेगा तब भारत विकासशील से विकसित भारत हो जाएगा।

एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया यह तकनीकी या प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। कहने का तात्पर्य विज्ञान, खोज (डिस्कवरी) पर आधारित होता है। प्रौद्योगिकी या तकनीकी, आविष्कार पर आधारित होता है। विज्ञान साक्ष्य के आधार पर एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करते हुए प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के ज्ञान और समझ की खोज और अनुप्रयोग है। प्रौद्योगिकी व्यावहारिक उद्देश्यों या अनुप्रयोगों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग है, चाहे वह उद्योग में हो या हमारे रोजमर्रा के जीवन में। इसलिए, मूल रूप से, जब भी हम किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने

वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे होते हैं। थॉमस एडिसन को प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। गैलीलियो को विज्ञान का जनक कहा जाता है। विज्ञान के विकास से प्रौद्योगिकी का विकास होता है क्योंकि बहुत सारी प्रौद्योगिकियाँ वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित होतीं हैं। 28 फ़रवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव (रमन इफ़ेक्ट) के खोज की घोषणा की थी। अतएव राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष की फ़रवरी माह के 28 तारीख को मनाया जाता है। स्वदेशी तकनीकी अर्थात अपने देश में निर्मित तकनीकी का इस्तेमाल करना या कराना। जब हम अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ किसी भी स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं तो विकास की पूरी संभावना होती है। बिना अध्यात्म का विकास, विनाश का कारण बनता है। भारत एक आध्यात्मिक देश है। अतएव यहां स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल भारत को पूर्णरूप से विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करेगा। भारत का चंद्रयान-3 मिशन स्वदेशी तकनीकी का सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण है। चंद्रयान-3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन था जो 24 अगस्त, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान लैंडर से नीचे उतर गया था और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश हो गया है। चंद्रयान-3 चाँद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का दूसरा प्रयास था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग भारत के लिए राम बाण साबित होगा। अभी हाल ही में तीन स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां- थर्मल कैमरा, सीएमओएस कैमरा और फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम- 4 फ़रवरी 2024 को भारत में 12 उद्योगों को हस्तांतरित कर दी गईं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत @ 2047 पहल के नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय की दिशा में एक कदम है। पहली तकनीकी- थर्मल स्मार्ट कैमरे में विभिन्न एआई आधारित एनालिटिक्स चलाने के लिए एक इनबिल्ट डीपीयू है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग स्मार्ट शहरों, उद्योगों, रक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए लक्षित किया गया है।

2047 तक देश को दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना मोदी का लक्ष्य हैं - साय

भाजपा ने किया विकसित भारत संकल्प सुझाव अभियान का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री रामविचार नेताम, प्रेमप्रकाश पांडेय, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा,संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, भरतलाल वर्मा ने विकसित भारत संकल्प सुझाव अभियान का शुभारंभ भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एलईडी स्क्रीन को हरी झंडी दिखाते हुए किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में दो बार 2014 एवं 2019 भाजपा की सरकार बनी और आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए भाजपा एकजुट हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत की इकोनॉमी 11वें पायदान पर थी जो अब पांचवें पायदान पर आ पहुंची है और 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को दुनिया के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास की ध्येय के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तेजी से विकास किया है। इन 10 वर्षों में कई जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाजपा की यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और गरीबों के उत्थान के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे उज्जवला गैस योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जैसे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया। वहीं जब दूसरी बार 2019 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब भी कई बड़े-बड़े काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किये जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण, कश्मीर से 370 की समाप्ति, तीन तलाक की समाप्ति जैसे कई बड़े-बड़े कदम उठाए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2014 में जनता के आशीर्वाद से भाजपा को 282 सीट में जीत मिली, वहीं 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने फिर से पसंद करते हुए 303 सीटों में कमल खिलाकर फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने इसलिए भाजपा अभी से जुट गई है और इस बार भाजपा का नारा है फिर एक बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ किया। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने सोमवार (26 फरवरी) को इस अभियान की शुरूआत राष्ट्रीय स्तर पर की है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान के माध्यम से आम लोगों से सुझाव एकत्रित करने के इस अभियान के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव एकत्रित करने के लक्ष्य के साथ इस अभियान में जुट चुकी है। उन्होंने बताया किया प्रथम चरण में विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभांरभ राष्ट्रीय स्तर पर 26 फरवरी को हुआ तत्पश्चात 27 व 28 फरवरी को प्रदेश स्तर पर इस कार्यक्रम के लॉन्चिंग की तारीख के तहत आज हम छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत कर रहे है और इसी कार्यक्रम को जिला स्तर पर आगे बढ़ाते हुए 28 व 29 फरवरी को जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की लॉन्चिंग होगी (सांसद, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति में लॉचिंग एवं प्रेसवार्ता की जाएगी।) भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बताया कि द्वितीय चरण में 27 फरवरी से 15 मार्च तक विकसित भारत संवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न संस्थाओं के ज्ञापन एवं सुझाव लेना और विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों में हम जुटेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। साथ ही एलईडी प्रचार वाहनों के माध्यम से देश भर के 500 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया जाएगा और छोटी सभाएं आयोजित कर जनता से सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। घर-घर जनसंपर्क अभियान 08 मार्च से 10 मार्च किया जायेगा, इस अभियान के तहत हम भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तरीय जनसंपर्क अभियान में निकल कर सघन जनसंपर्क करेंगे और जनता से सुझाव एकत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों के कार्यक्रम 27 फरवरी से 15 मार्च तक विभिन्न प्रकोष्ठ द्वारा इस अभियान के तहत जिला स्तरीय गोष्ठी एवं विधानसभा स्तर पर छोटी बैठकों के माध्यम से संबंधित सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कहा कि इसके लिए देश भर के लोगों से सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनजुड़ाव, जनसंवाद और जनता से सतत संपर्क पर विश्वास रखती है और इसलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जनता से संवाद आगे बढ़ाने और जनता के सुझाव एकत्रित करने के लिए भाजपा हर एक माध्यम को अपने इस अभियान में शामिल किया है जिसके अंतर्गत जनसंपर्क गतिविधियां (सीधा संवाद) संवाद, घर-घर जनसंपर्क, प्रकोष्ठों के कार्यक्रम, लाभार्थी संपर्क अभियान के साथ ही डिजिटल माध्यम से भी संपर्क किया जाएंगे। नमो एप्प, मिस्डकॉल नंबर (909090-2024), सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सुझाव आमंत्रित है। उन्होंने बताया कि प्रचार के कई माध्यम है जैसे एलईडी प्रचार वाहन (देश भर में 500 एलईडी प्रचार वाहनों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे है। छत्तीसगढ़ में भी सभी लोकसभा क्षेत्रों में एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से हम पहुंचेंगे। देश भर में 6 हजार सुझाव पेटी के माध्यम से सुझाव एकत्रित किए जा रहे है।

इस दौरान विकसित भारत संकल्प सुझाव अभियान का शुभारंभ में मंत्री केदार कश्यप श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल,वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, भावना बोहरा, पुरंदर मिश्रा, खुशवंत साहेब संदीप शर्मा, सौरभ सिंह, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, मोतीलाल साहू, गोमती साय, नीलकंठ टेकाम, यशवंत जैन, किशोर महानंद, मधुसूदन यादव, अनुराग सिंह देव, रजनीश सिंह, शंकर अग्रवाल, सहित भाजपा भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,नितिन नबीन, किरण सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर किया रथ रवाना

एलईडी प्रचार वाहनों के माध्यम से देशभर के 500 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया जाएगा - किरण सिंह देव

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह का सपना पूरा हो रहा है। योजना के तहत बालोद जिले में मंगलवार को 185 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बँधे।

संदेशखाली: दो-चार सीट पाने महिलाओं के साथ रहे अत्याचार

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व विधायक रंजना साहू ने संदेशखाली पश्चिम बंगाल पर कल के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बयान पर कहा कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में दो-चार सीट पाने के लिए महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और अत्याचार का बचाव कर रही है छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जब जनजाति समाज के साथ पश्चिम बंगाल में हो रहे दुष्कर्म पर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर ममता बनर्जी को पत्र लिखा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है चाटुकारिता कांग्रेस के डीएनए में है जनता से इन्हें मतलब नहीं महिला सुरक्षा और महिला अत्याचार पर कांग्रेस का इस प्रकार का स्टैंड कांग्रेस के महिला विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है महिलाएं इसका जवाब जरूर देंगी।

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा की मेराथन बैठकें हुई

विस में मिली प्रचंड जीत से कार्यकर्ता उत्साहित, 11 की 11 सीटे जीतेंगे

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दिनभर मेराथन बैठकों का दौर चला। विभिन्न स्तरों में आहूत इन मेराथन बैठकों में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब तक के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। इन सभी बैठकों में चुनाव समिति के पदाधिकारीगण प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्रीगण संजय श्रीवास्तव, भरतलाल वर्मा, जगदीश (रामू) रोहरा व रामजीलाल भारती, सभी मोर्चों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सवन्नी व सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा ,सौरभ सिंह, रजनीश सिंह सहित सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक शिवरतन शर्मा, समस्त प्रकोष्ठों के

संयोजक सहित वरिष्ठ जन मौजूद थे। भाजपा की मेराथन बैठकों की श्रृंखला में सबसे पहले क्लस्टर प्रभारियों, लोकसभा प्रभारियों, लोकसभा संयोजकों व सह संयोजकों की बैठक हुई। इसके बाद दूसरी बैठक भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों की टोलियों की हुई। इसके बाद भाजपा के सभी मोर्चों के प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री, संभाग प्रभारियों के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों की बैठक रखी गई है। सबसे अंत में प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। चुनाव तैयारियों के दृष्टिगत ये बैठकें काफी अहम रहीं और इनमें चुनावी रणनीति के मार्गदर्शक बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इन बिन्दुओं के आलोक में मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे जाएंगे। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नवीन ने अब तक हुए संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा कर बैठकों में उपस्थित पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति के मार्गदर्शक बिंदुओं से अवगत कराया। नवीन ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जन-आशीर्वाद से हासिल ऐतिहासिक जनादेश से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए अबकी बार चार सौ पार का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में सभी भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को कटिबद्ध होकर उतरना है। इन मेराथन बैठकों के बाद भाजपा चुनावी तैयारियों में काफी तेजी से आगे चल रही है जबकि कांग्रेस पराजित मनोबल और हताशा की शिकार दिखाई पड़ रही है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों और मोदी की गारंटी पर तेजी से काम करती महज दो माह पुरानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व जन विश्वास अर्जित किया है और इसका सुपरिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में साफ नजर आएगा। अब कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री मोदी का संदेश लेकर घर-घर पहुँचें और प्रदेश में भाजपा की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करें।

प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सह प्रभारी नितिन नबीन ,प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह उपमुख्यमंत्री द्वय अरुण साव व विजय शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय डॉ. सरोज पांडेय व सुश्री लता उसेंडी, मंत्रीगण ओ.पी. चौधरी, रामविचार नेताम व केदार कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, रामप्रताप सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत की उपस्थिति रही।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कोयलीबेड़ा नक्सली मुठभेड़ की जांच हेतु समिति का गठन

रायपुर। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोमरा हुरतराई मिच्चेबेड़ा एवं आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान कथित नक्सली मुठभेड़ में तीन ग्रामीणों की हुई मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी के नेतृत्व में सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति में पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी संयोजक, पूर्व विधायक संतराम नेताम सदस्य, पूर्व विधायक शंकरलाल ध्रुव सदस्य, प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर सदस्य, प्रदेश महामंत्री नरेश ठाकुर सदस्य, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रूपसिंह पोटाई सदस्य, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभद्रा सलाम सदस्य है। जांच समिति के सदस्यों को कहा गया है कि वे अविलंब प्रभावित गामों का दौरा कर पीड़ित परिजनों सहित स्थानीय ग्रामवासियों से भेंट एवं चर्चा कर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रेषित करें।

ज़ब मुख्यमंत्री निवास ही सुरक्षित नहीं ऐसे में आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री निवासी ही सुरक्षित नहीं है, पिस्तौल लेकर लोग वहां पहुंचे जा रहे हैं ऐसे में आम जनता की सुरक्षा तो भगवान भरोसा हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। 3 महीने में तीन दर्जन से अधिक हत्या हो गई है। नक्सली वारदात, चाकू बाजी, लूटपाट, अपहरण, रेप-गैंगरेप की घटनाएं बढ़ गई। सूदखोर भूमाफिया का आतंक बढ़ गया हैं। गृह मंत्री के गृह जिला कवर्धा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति की तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई, बलौदा बाजार जिला में घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या कर दी गई, दो लोग घायल हैं, भाजपा के विधायक पुलिस के अधिकारी को देख लेने की धमकी देते हैं। भाजपा से जुड़े नेता 6 वर्ष की मासूम का किडनैप कर फिरौती नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर देता है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आम जनता अपने जान माल को लेकर चिंतित है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सरकार के दौरान कानून मजबूती से काम कर रहा था अपराधियों में कानून का भय दिखता था।

ढाई महीने में ही हांफने लगी है सरकार, ले चुकी है 13000 करोड़ का नया कर्ज

रायपुर। वित्तमंत्री ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि तथाकथित डबल इंजन की भाजपा सरकार ढाई महीने में ही हांफने लगी है। विष्णुदेव साय सरकार से ना प्रदेश संभल रहा है ना ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भाजपा सरकार की ना अपनी कोई अपनी योजना छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से धरातल पर उतारी जा सकी है और ना ही ये पूर्ववर्ती सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से संचालित कर पा रहे हैं। बेरोजगारों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता नवंबर माह से बंद है जिसका बजट प्रावधान पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक के लिए किया गया था। यही नहीं विगत खरीफ़ सीजन के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि भी भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने हड़प लिया। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी जाने वाली राहत और सब्सिडी को बंद करके भाजपा की विष्णुदेव सरकार केवल भ्रष्टाचार के लिए कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है। विगत डेढ़ माह के भीतर ही साय सरकार ने 13000 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज़ लिया है।

तस्करी कर लाई गई 3.89 करोड़ से अधिक की विदेशी सिगार समेत 41 लाख सिगरेट की गई नष्ट

रायपुर। सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर (भोपाल जोन) द्वारा बुधवार को रायपुर में 3.89 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मूल सिगार और विदेशी मूल रोलिंग पेपर के साथ तस्करी कर लाई गई विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट नष्ट की गई है. विदेशी मूल की सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात के खिलाफ एक अभियान में भोपाल जोन में सीमा शुल्क आयुक्तालय, इंदौर ने रायपुर छत्तीसगढ़ में भट्टी में जलाकर विदेशी मूल की 40.86 लाख सिगरेट को नष्ट कर दिया. जानकारी के मुताबिक, इन सिगरेट के साथ ही भारत में तस्करी करके लाए गए 2000 विदेशी मूल के सिगार और 557 विदेशी मूल के रोलिंग पेपर के बक्सों को भी नष्ट कर दिया गया. नष्ट की गई सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग रु. 3.89 करोड़ रूपए है. इन्हें भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करके भारत में तस्करी कर लाया गया था. जब्त सिगरेट, सिगार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 (संशोधित) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं थे. जब्त की गई सिगरेट, सिगार और रोलिंग पेपर वैधानिक मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए वैधानिक मेट्रोलॉजी (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुरूप भी नहीं थे.

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बैज का तंज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में चूक मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। प्रदेश सरकार खुद की सुरक्षा करने में नाकामयाब है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में बीजेपी की बैठक को लेकर कहा कि बीजेपी डरी हुई है। इस बैठक का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मार्च के पहले सप्ताह में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि नाम जा चुके हैं। इसके अलावा भी जहां संभावनाएं हैं, वहां से दावेदार सामने आ रहे हैं। आदिवासी बच्चों के साथ गृहमंत्री विजय शर्मा के लंच को लेकर दीपक बैज ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इतने ही आदिवासी हितैषी हैं, तो हसदेव के आदिवासियों के साथ खड़े हो जाएं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्यसभा में हिमाचल के नतीजे आए वह आश्चर्यजनक है। बीजेपी के मुखिया प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाने किसी भी हद तक जा सकते हैं। केवल हिमाचल में ही नहीं बल्कि देश में हर जगह ये डराने-धमकाने का काम कर रहे हैं। ये आगे भी ऐसा करेंगे।

पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ग्राम मुरा में मीडियाकर्मियों से चर्चा में कहा

सनातन मूल्यों की स्थापना से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव

रायपुर। श्री गोवर्धनमठ पुरीपीठाधीश्वर श्रीमदगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज ग्राम मुरा, खरोरा पहुंचे। यहां वे राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आयोजित धर्म महासभा में हिस्सा लेंगे। आज मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि सनातन को मानने से ही व्यक्ति का उत्कर्ष हो सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहां इसका पालन नहीं हो रहा है वहां अव्यवस्था है। संस्कार नष्ट हो रहा है। सनातन मूल्यों की स्थापना से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है।

इस आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के प्रदेश संयोजक तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्र ने बताया कि राष्ट्रोत्कर्ष अभियान अंतर्गत सनातन मूल्यों और राष्ट्र चेतना के विकास के लिए ग्राम मुरा में धर्म महासभा का आयोजन किया गया है। इसमें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज सनातन मूल्यों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगे। हमारे कई जन्मों का पुण्य फल उदित हुआ है कि महाराज जी यहां पधारे हैं। यह पूरा क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है।

श्री मिश्र ने बताया कि राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के अंतर्गत हम सनातन मूल्यों को सुदृढ़ करने कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हमारी सनातन परंपरा के गहरे मूल्यों के संबंध में प्रकाश डालेंगे। श्री मिश्र ने बताया कि आयोजन पंडित लखनलाल मिश्र पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में पूर्वान्ह साढ़े ग्यारह बजे किया जा रहा है। ग्राम मुरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित लखनलाल मिश्र की पुण्यभूमि है। इस पुण्यभूमि में यह सुंदर आयोजन किया जा रहा है जो निश्चित रूप से राष्ट्रोत्कर्ष के अभियान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगले दिन पंडित लखनलाल मिश्र सेवा परिसर में दर्शन, संगोष्ठी एवं दीक्षा का कार्यक्रम किया जाएगा।

आज भी प्रासंगिक हैं राजिम का लोमष ऋषि आश्रम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाले पावन नगरी राजिम में भगवान वास करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान श्री राजीव लोचन और श्री कुलेश्वर महादेव है, जिसके आशीर्वाद से हर वर्ष राजिम मेला बिना किसी रूकावट के संपन्न होता है। इसके साथ ही प्रयाग क्षेत्र में स्थित लोमष ऋषि आश्रम है। लोमष ऋषि आश्रम के संदर्भ में कई किवदंतियाँ है। मान्यता है कि आज भी लोमष ऋषि सबसे पहले भगवान राजीव लोचन भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसके कुछ साक्ष्य यहां के पुजारियों को परिलक्षित हुए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम वन गमन के दौरान कुछ दिनों तक राजिम स्थित लोमष ऋषि के आश्रम में ठहरे थे और यहीं पर चित्रोत्पला गंगा महानदी की रेत में शिवलिंग

बनाकर पूजा-आराधना की थीं। जिन्हें वर्तमान में कुलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। राजिम के कुछ बुजुर्गो ने यहां तक दावा किया है कि सुबह नदी में कभी भी अचानक लंबे पैरो के निशान दिखाई देते हैं जो संभवतः लोमष ऋषि के ही हो सकते हैं। आज भी राजिम में लोमष ऋषि का आश्रम विद्यमान है। यहां उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित हैं जिनकी नित्य पूजा अर्चना किया जाता है। यहां पर बेल के अत्यधिक पेड़ होने के कारण इसे बेलाही घाट भी कहा जाता हैं। प्राकृतिक दृष्टि से भी यह बहुत मनोहारी है यहां आने से एक प्रकार से शांति का अनुभव होता है। राजिम कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था, श्रद्धा और आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यह आकर श्रद्धालु घंटो समय व्यतीत करता है और अपनी थकान मिटाकर अपनी गणतव्य की आगे बढ़ते हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.